सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 140, नई दिल्ली । बुधवार, 31 जुलाई 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अपने किरदार की हिफाजत जान से बढ़कर कीजिये, क्योंकि इसे जिंदगी के बाद भी याद किया जाता है।

03 कोचिंग मामले में पुलिस ने सात लोगों को किया गिरफ्तार, अब तक क्या-क्या हुआ?
06 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है नए अवसर
08 जहाज को तुरंत गिरफ्तार किया जाए : ओड़िशा हाई कोर्ट

दिल्ली की सड़कों पर उतरा 320 इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा, एलजी और परिवहन मंत्री ने दिखाई हरी झंडी

बजट में पुरानी योजनाओं को पूरा करने पर जोर एनसीआरटीसी को 3596 करोड़ मिले, मेट्रो फेज चार का बढ़ेगा नेवटर्क

संजय बाटला

दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों का एक और बेड़ा सड़क पर उतर गया है। एलजी और परिवहन मंत्री ने मंगलवार को हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। बसों के सड़क पर उतरने के बाद दिल्लीवासियों की यातायत को लेकर सुविधा काफी हद तक सुधर जाएगी। हालांकि अभी और भी बसें दिल्ली परिवहन विभाग में शामिल की जाएंगी।

नई दिल्ली। दिल्ली के परिवहन विभाग में इलेक्ट्रिक बसों का एक और बेड़ा शामिल हो गया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत मंगलवार को हरी झंडी दिखा दी। दिल्ली की सड़कों पर जब ये बसें दौड़ेंगी तो यात्रियों की समस्या कुछ हद तक दूर होगी।

दिल्ली के परिवहन मंत्री ने सोशल साइट एक्स पर इसकी जानकारी दी। फोटो शेयर करते हुए लिखा, दिल्लीवासियों को बधाई ! आज एलजी के साथ 320 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया। इसके साथ ही दिल्ली में अब इलेक्ट्रिक बसों की कुल संख्या 1970 हो गई है। यह पूरे देश में किसी भी शहर के मुक़ाबले इलेक्ट्रिक बसों की सर्वाधिक संख्या है।

दिल्ली में अब कुल 7683 बसें दिल्लीवासियों की सेवा में सड़कों पर हैं। केजरीवाल सरकार दिल्लीवासियों को विश्वस्तरीय, प्रदूषणमुक्त, सुगम परिवहन सेवा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)
TOLWA
website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com
रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण
रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

डॉ. लॉजिस्टिक्स : भारत में फ्रेट कॉरिडोर का काम और इलाहाबाद में फ्रेट कॉरिडोर ऑफिस का योगदान : डॉ. अंकुर शरण

फ्रेट कॉरिडोर भारत के लॉजिस्टिक्स और परिवहन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह प्रणाली देशभर में माल ढुलाई को अधिक कुशल और प्रभावी बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है। भारत में दो प्रमुख फ्रेट कॉरिडोर हैं: पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (Western Dedicated Freight Corridor - WDFC) और पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (Eastern Dedicated Freight Corridor - EDFC)। इन कॉरिडोर्स का मुख्य उद्देश्य है भारी और लंबे माल की आवाजाही को सुविधाजनक बनाना और ट्रैफिक जाम और समय की बर्बादी को कम करना।

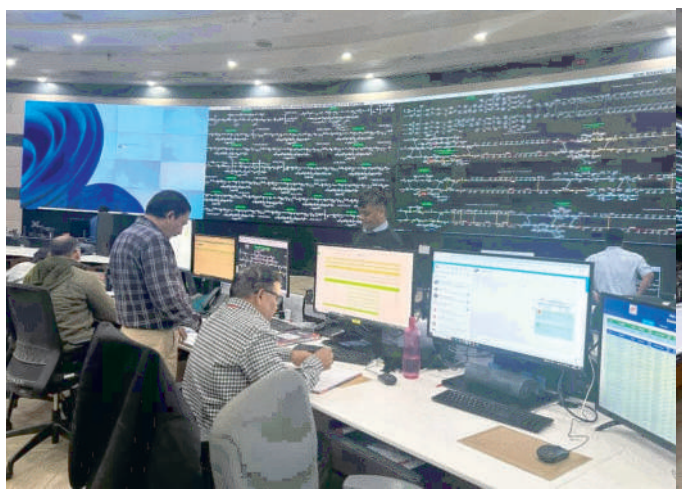

भारत में फ्रेट कॉरिडोर का काम

माल ढुलाई की दक्षता में सुधार: फ्रेट कॉरिडोर विशेष रूप से मालगाड़ियों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इससे माल की ढुलाई अधिक तेज़ और कुशल हो जाती है। पारंपरिक रेल नेटवर्क की तुलना में, ये कॉरिडोर अधिक क्षमता वाले हैं और इसमें माल गाड़ियों की आवाजाही के लिए अधिक सुविधा है।

लागत में कमी: फ्रेट कॉरिडोर माल ढुलाई की लागत को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह उद्योगों को अपने उत्पादों को बाजार में अधिक किफायती ढंग से लाने में मदद करता है, जिससे कुल उत्पादन लागत में कमी आती है।

पर्यावरणीय लाभ: फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से ट्रकों की तुलना में अधिक मालगाड़ियों का उपयोग किया जाता है, जिससे ईंधन की खपत कम होती है और कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है। यह पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देता है।

सड़क यातायात का कम होना: माल की बड़ी मात्रा को फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है, जिससे सड़कों पर ट्रकों का बोझ कम होता है। इससे सड़क यातायात की स्थिति में सुधार होता है और दुर्घटनाओं का जोखिम कम होता है।

इलाहाबाद में फ्रेट कॉरिडोर ऑफिस का योगदान

इलाहाबाद में स्थित फ्रेट कॉरिडोर ऑफिस, विशेष रूप से पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (EDFC) के लिए महत्वपूर्ण है। इस ऑफिस का मुख्य उद्देश्य है EDFC की परियोजना को संचालन और प्रबंधन में सहायता प्रदान करना। इस कार्यालय के योगदान को निम्नलिखित बिंदुओं में विभाजित किया जा सकता है:

प्रोजेक्ट मैनेजमेंट: इलाहाबाद ऑफिस फ्रेट कॉरिडोर परियोजना की योजना, क्रियान्वयन, और निगरानी के लिए जिम्मेदार है। यह परियोजना के विभिन्न चरणों में गुणवत्ता नियंत्रण और समय प्रबंधन सुनिश्चित करता है।

इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट: यह कार्यालय विभिन्न रेलवे स्टेशनों, सिग्नल सिस्टम्स, और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास और रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे ट्रेन परिचालन में सुधार होता है और माल ढुलाई की प्रक्रिया को सुगम बनाता है।

सुरक्षा और ट्रेनिंग: इलाहाबाद ऑफिस सुरक्षा मानकों का पालन करने और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए भी जिम्मेदार है। यह सुनिश्चित करता है कि मालगाड़ियों का संचालन सुरक्षित और कुशल तरीके से हो।

समुदाय और उद्योग के साथ सहभागिता: यह कार्यालय स्थानीय समुदाय और उद्योगों के साथ समन्वय करता है ताकि फ्रेट कॉरिडोर परियोजना से संबंधित मुद्दों और चुनौतियों का समाधान किया जा सके।

भारत में फ्रेट कॉरिडोर देश की लॉजिस्टिक्स और परिवहन व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं। यह कॉरिडोर न केवल माल ढुलाई की दक्षता में सुधार करते हैं, बल्कि लागत में कमी, पर्यावरणीय स्थिरता, और सड़क यातायात को कम करने में भी मदद करते हैं। इलाहाबाद में स्थित फ्रेट कॉरिडोर ऑफिस विशेष रूप से EDFC के संचालन और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे इस परियोजना की सफलता सुनिश्चित होती है। इस प्रकार, फ्रेट कॉरिडोर भारत के लॉजिस्टिक्स के भविष्य को नया आयाम देने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं।

ankur.supplychain@gmail.com

संबलपुर में मालगाड़ी पटरी से उतरी ओड़िशा में चार दिन में चार रेल हादसे

मनोरंजन सासमल , स्टेटे हेड उडीशा

भुबनेश्वर : संबलपुर में मालगाड़ी पटरी से उतरी । सरला के पास एक बुग्गी पटरी से उतर गई है। रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंच कर जांच कर रहे हैं। समाचार लिखे जाने तक, क्षति की कोई रिपोर्ट नहीं थी हालांकि, मंगलवार सुबह करीब 3:45 बजे झारखंड में हावड़ा-म्यू नोई एक्सप्रेस पटरी से उतर गई ।जब ट्रेन पटरी से उतरी तो दूसरी लाइन पर खड़ा मालवाहक ट्रेन से टकरा गया। एक्सप्रेस के पांच डिब्बे पटरी से उतर गए । इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए ।3 मृतकों में से दो राउरकेला के हैं ।

भुवनेश्वर के वाणीबिहार स्टेशन पर एक हादसा हो गया

मनोरंजन सासमल , स्टेटे हेड उडीशा, भुबनेस्वर : मंगलवार को भुवनेश्वर के वाणीबिहार स्टेशन पर एक हादसा हो गया । ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी युवक ने रेल लाइन पर सोते समय आत्महत्या कर ली । हालांकि अभी तक युवक की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि उसने प्रेम संबंधों के चलते आत्महत्या की है । पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी।

"सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा" सड़क पर किस बात की जल्दी है, जिनको जल्दी थी वो चले गए

सड़क पर जल्दबाज़ी और आवेश का मिला-जुला परिणाम है रोड रेज, जो न केवल वाहन चालकों के लिए बल्कि पैदल यात्रियों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। 'सड़क पर किस बात की जल्दी है, जिनको जल्दी थी वो चले गए'—यह कहावत आज के समय में बहुत प्रासंगिक है, खासकर जब सड़कों पर गाड़ी चलाते समय धैर्य और संयम का पालन न करने से लोगों की जान पर बन आती है।

डॉ. अंकुर शरण

सड़क सुरक्षा का महत्व आज के दौर में पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। ₹सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा₹ सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है जो हर वाहन चालक और पैदल यात्री पर लागू होती है। हर साल, सड़क दुर्घटनाओं के कारण हजारों लोग अपनी जान गंवाते हैं और कई लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। ये घटनाएं न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी गंभीर प्रभाव डालती हैं।

सड़क पर जल्दबाज़ी और आवेश का मिला-जुला परिणाम है रोड रेज, जो न केवल वाहन चालकों के लिए बल्कि पैदल यात्रियों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। 'सड़क पर किस बात की जल्दी है, जिनको जल्दी थी वो चले गए'—यह कहावत आज के समय में बहुत प्रासंगिक है, खासकर जब सड़कों पर गाड़ी चलाते समय धैर्य और संयम का पालन न करने से लोगों की जान पर बन आती है।

रोड रेज के कारण:

अधीरता: आज की तेज़-तर्रार जिंदगी में लोग जल्द से जल्द अपने गंतव्य तक पहुँचने की कोशिश में रहते हैं। समय की कमी और अधीरता अक्सर ड्राइविंग के दौरान गलत फैसले लेने का कारण बनती है।

तनाव और मानसिक दबाव: मानसिक तनाव और दबाव की स्थिति में लोग आसानी से गुस्से में आ जाते हैं, जो ड्राइविंग के दौरान रोड रेज का रूप ले लेता है।

ट्रैफिक जाम: बड़े शहरों में बढ़ते ट्रैफिक जाम और धीमी गति से चलने वाले यातायात की वजह से लोग जल्द ही चिढ़ जाते हैं, जिससे झगड़े की संभावना बढ़ जाती है।

रोड रेज के परिणाम:

हादसे और दुर्घटनाएं: गुस्से में तेज़ी से गाड़ी चलाना, अचानक ब्रेक लगाना, या बिना सोचे-समझे ओवरटेक करना गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है।

शारीरिक हिंसा: रोड रेज के मामलों में अक्सर लोग एक-दूसरे से उलझ जाते हैं, जो शारीरिक हिंसा का रूप ले सकता है।

मनोवैज्ञानिक प्रभाव: ऐसे घटनाओं के बाद मानसिक रूप से प्रभावित होने की संभावना भी बढ़ जाती है, जो भविष्य में लोगों की ड्राइविंग क्षमता पर असर डाल सकती है।

समाधान और सुझाव:

धैर्य और संयम: ड्राइविंग करते समय हमेशा धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। जल्दबाज़ी न करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें।

मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान: मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें और तनाव को कम करने के उपाय अपनाएं।

स्वयं को शांत रखें: यदि कोई दूसरी गाड़ी चालक आपको परेशान कर रहा है, तो जवाबी प्रतिक्रिया न दें। शांत रहें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें।

सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता: लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सामाजिक और शैक्षिक अभियानों का आयोजन किया जाना चाहिए।

अंत में, याद रखें कि सड़क पर हर किसी की सुरक्षा आपके हाथ में है। अपनी और दूसरों की जिंदगी की कीमत को समझें और सड़क पर धैर्य और शांति से गाड़ी चलाएं। ₹जिनको जल्दी थी वो चले गए₹—इस कहावत से सीख लें और सड़क पर अपने गुस्से को नियंत्रित करें, ताकि हम सभी सुरक्षित रह सकें।

roadsafetysquad@gmail.com

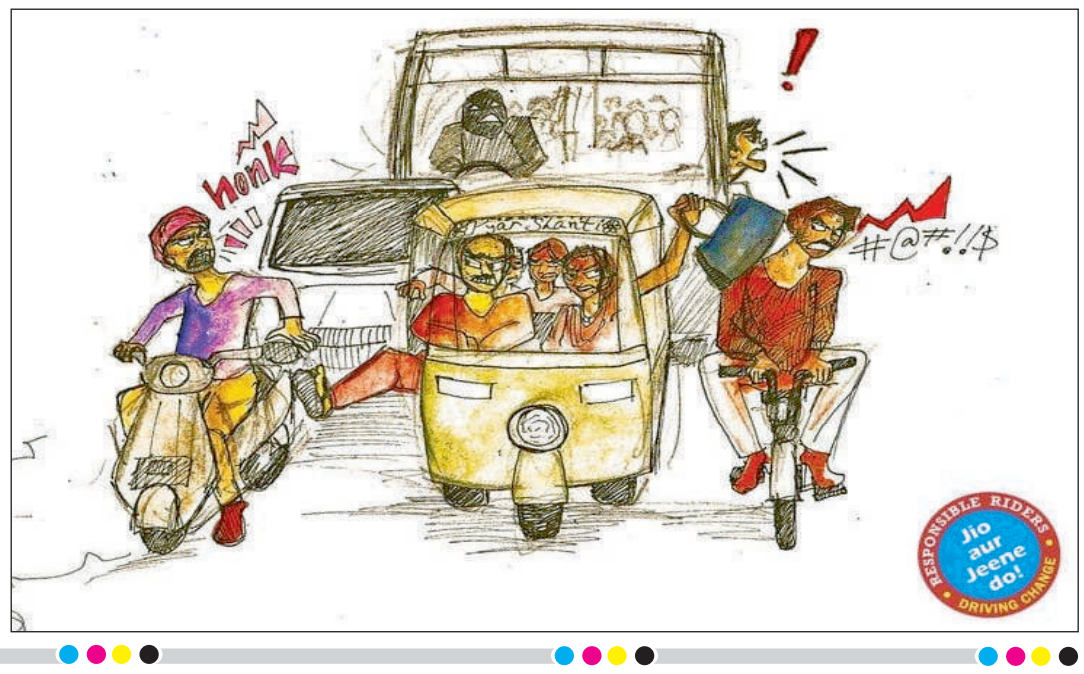

नथिंग फ़ोन 2ए प्लस भारत में 31 जुलाई को लॉन्च होगा, जानिए कैमरा और प्रोसेसर की जानकारी

कार्ल पेई की नथिंग 31 जुलाई को भारत में नथिंग फोन (2ए) प्लस लॉन्च करने के लिए तैयार है। अपग्रेड में डुअल 50MP रियर कैमरा, 50MP फ्रंट कैमरा और मीडियाटेक डाइमेंशन 7350 चिपसेट शामिल है।

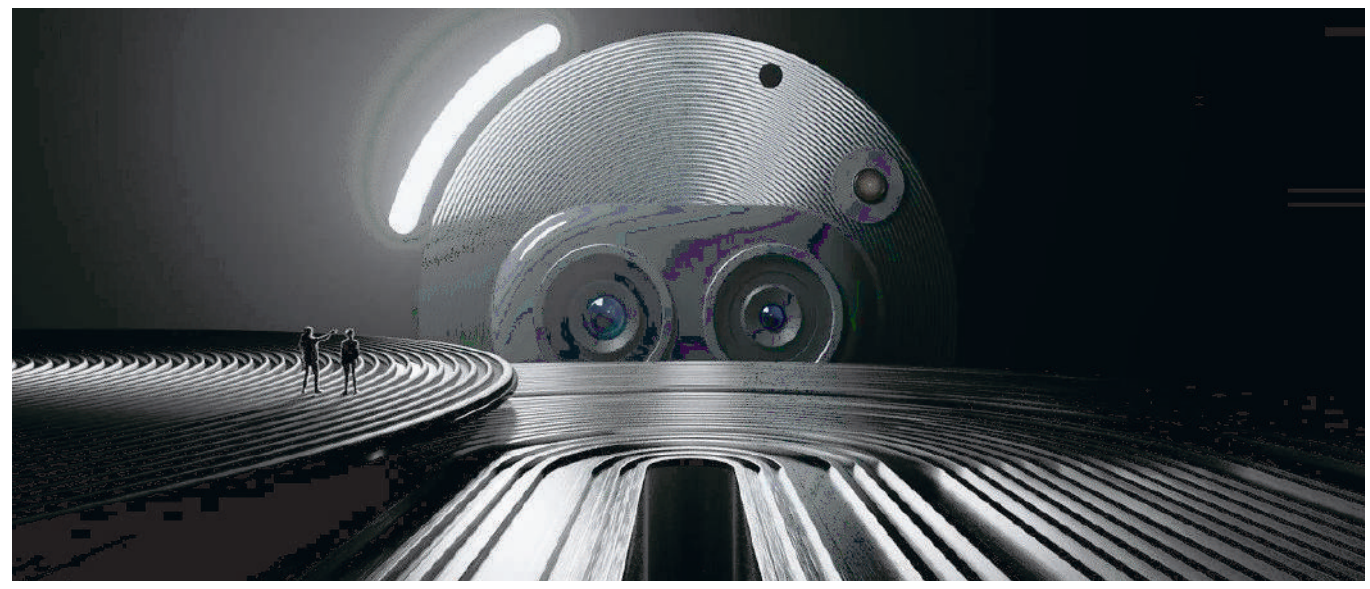

31 जुलाई को भारत में अपने नवीनतम स्मार्टफोन, नथिंग फोन (2ए) प्लस की रिलीज के लिए तैयार हो रहा है। नथिंग फोन (2ए) की मार्च की शुरुआत के बाद, नए मॉडल की उम्मीद है कई वृद्धि लाएं। यूके स्थित कंपनी ने पहले आगामी डिवाइस के चिपसेट और रैम के बारे में विवरण का खुलासा किया है। हाल ही में, उन्होंने इसके कैमरा सिस्टम के बारे में जानकारी का अनावरण किया और रियर कैमरा डिज़ाइन की एक झलक प्रदान की।

नथिंग फोन 2ए प्लस के कैमरा स्पेसिफिकेशन

नथिंग फोन (2ए) प्लस में डुअल रियर कैमरा सेटअप होगा, जिसमें दो 50MP सेंसर होंगे, जो मूल फोन (2ए) के कॉन्फ़िगरेशन को प्रतिबिंबित करेंगे। हालांकि, फ्रंट कैमरे को एक महत्वपूर्ण अपग्रेड मिलने वाला है। फ़ोन (2a) के विपरीत, जिसमें 32MP का फ्रंट कैमरा है, (2a) प्लस 50MP के फ्रंट-फेसिंग सेंसर के साथ आएगा।

इन कैमरा विवरणों की पुष्टि करने वाले एक्स पर एक पोस्ट में रियर कैमरा डिजाइन का एक टीजर भी दिखाया गया है। लेआउट, जिसमें सेंसर प्लेसमेंट और एक ग्लिफ़ इंटरफ़ेस एलईडी यूनिट शामिल है, फोन (2ए) के रियर कैमरा मॉड्यूल से काफी मिलता जुलता है।

नथिंग फोन 2ए प्लस की अपेक्षित विशेषताएं

कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, नथिंग फोन (2ए) प्लस मीडियाटेक डाइमेंशन 7350 चिपसेट द्वारा संचालित होगा जो 12GB तक रैम के साथ जुड़ा होगा। लीक से पता चलता है कि फोन दो कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध होगा 256GB स्टोरेज के साथ 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ 12GB रैम। यह कथित तौर पर ब्लैक और ग्रे कलर वेरिएंट में आएगा। हैंडसेट में अपने पूर्ववर्ती के समान 120Hz रिफ्रेश रेट और इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ 6.7-इंच AMOLED डिस्प्ले होने की भी उम्मीद है।

इसके अतिरिक्त, लीक से संकेत मिलता है कि नथिंग फोन (2a) प्लस 50W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर सकता है, जो फोन (2a) की 45W फास्ट चार्जिंग क्षमता में सुधार है। मौजूदा मॉडल की तरह, प्लस वेरिएंट 5,000mAh की बैटरी से लैस होने की संभावना है। जैसे-जैसे लॉन्च की तारीख नजदीक आ रही है, नथिंग फोन (2ए) प्लस बाजार में जो वृद्धि और नई सुविधाएं लाएगा, उसे लेकर प्रत्याशा बढ़ रही है।

मानसून के दौरान ऑयली स्किन से कैसे निपटें?

मानसून के दौरान ऑयली स्किन के प्रबंधन के लिए एक बेहतरीन और अनुरूप त्वचा देखभाल दिनचर्या की आवश्यकता होती है। सही उत्पादों का चयन करके, स्वस्थ आहार बनाए रखकर और कुछ प्रभावी घरेलू उपचारों को शामिल करके, आप नमी के बावजूद अपनी त्वचा को ताजा और चमकदार बनाए रख सकते हैं।

मानसून का मौसम चिलचिलाती गर्मी से राहत तो देता है लेकिन ऑयली स्कीन वाले लोगों के लिए अनोखी चुनौतियां भी पेश करता है। इस मौसम के दौरान बढ़ी हुई आर्द्रता तेल उत्पादन को बढ़ा सकती है, जिससे दाने निकल सकते हैं और चिकनापन आ सकता है। मानसी शर्मा, संस्थापक, द ऑनेस्ट ट्री बाय बोडेस ब्यूटी ने मानसून में तैलीय त्वचा से निपटने के लिए सुझाव साझा किए हैं।

तैलीय त्वचा को समझना

तैलीय त्वचा की विशेषता अतिरिक्त सीबम उत्पादन है। सीबम, वसामय ग्रंथियों द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक तेल है, जो त्वचा को नमीयुक्त रखने में मदद करता है। हालांकि, जब अधिक मात्रा में इसका उत्पादन होता है, तो इससे रोम छिद्र बंद हो सकते हैं, मुंहासे हो सकते हैं और त्वचा चमकदार हो सकती है। मानसून का मौसम, अपने उच्च आर्द्रता स्तर के साथ, इन समस्याओं को और खराब कर सकता है, जिससे आपकी त्वचा की देखभाल की दिनचर्या को तदनुसार अनुकूलित करना महत्वपूर्ण हो जाता है।

मानसून में तैलीय त्वचा से निपटने के टिप्स

चेहरे की सफाई

गंदगी, तेल और अशुद्धियां हटाने के लिए दिन में दो बार अपना चेहरा साफ करें। ज्यादा धोने से त्वचा का प्राकृतिक तेल खत्म हो सकता है, जिससे त्वचा में और भी अधिक सीबम उत्पन्न होने लगता है।

प्रोडक्ट का चयन- तेल उत्पादन को नियंत्रित करने और मुँहासे को रोकने में मदद के लिए सैलिसिलिक एसिड या चाय के पेड़ के तेल के साथ एक सौम्य, सल्फेट-मुक्त क्लींजर का उपयोग करें।

एक्सफोलिएशन जरुरी

मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाने और बंद रोमछिद्रों को रोकने के लिए सप्ताह में 1-2 बार एक्सफोलिएट करें।

प्रोडक्ट का चयन- जलन पैदा किए बिना त्वचा को साफ रखने के लिए अल्फा हाइड्रॉक्सी एसिड (एएचए) या बीटा हाइड्रॉक्सी एसिड (बीएचए) वाला हल्का एक्सफोलिएटर चुनें।

टोनर का प्रयोग करें

टोनिंग त्वचा के पीएच को संतुलित करने और बची हुई अशुद्धियों को दूर करने में मदद करती है।

प्रोडक्ट का चयन- त्वचा को आराम देने और तैलीयपन को कम करने के लिए विच हेजल, ग्रीन टी या कैमोमाइल जैसी सामग्री वाले अल्कोहल-मुक्त टोनर का उपयोग करें।

मॉइस्चराइजिंग करना जरुरी

तैलीय त्वचा वाले बहुत से लोग इस डर से मॉइस्चराइजिंग करना छोड़ देते हैं कि इससे उनकी त्वचा तैलीय हो जाएगी। हालांकि, इस चरण को छोड़ने से डिहाइड्रेशन हो सकता है, जिससे त्वचा अधिक तेल का उत्पादन करने के लिए प्रेरित हो सकती है।

प्रोडक्ट का चयन- हल्के, गैर-कॉमेडोजेनिक, पानी-आधारित मॉइस्चराइजर का चयन करें जो छिद्रों को बंद किए बिना हाइड्रेट करता है।

धूप से सुरक्षा जरुरी

सनस्क्रीन लगाना बहुत ही जरुरी है सीजन चाहे कोई भी हो। सनस्क्रीन का प्रयोग पूरे साल महत्वपूर्ण है, जिसमें मानसून भी शामिल है।

प्रोडक्ट का चयन- अपनी त्वचा को चिकनाई बढ़ाए बिना सुरक्षित रखने के लिए कम से कम एसपीएफ 30 वाला ब्रॉड-स्पेक्ट्रम, तेल-मुक्त, मैट-फिनिश सनस्क्रीन चुनें।

मानसून के दौरान तैलीय त्वचा के प्रबंधन के लिए एक बेहतरीनऔर अनुरूप त्वचा देखभाल दिनचर्या की आवश्यकता होती है। सही उत्पादों का चयन करके, स्वस्थ आहार बनाए रखकर और कुछ प्रभावी घरेलू उपचारों को शामिल करके, आप नमी के बावजूद अपनी त्वचा को ताजा और चमकदार बनाए रख सकते हैं। इन टिप्स को अपनाएं और आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ मानसून के मौसम का आनंद लें।

अगस्त के महीने में फ्रेंडस के साथ जाएं देश की इन शानदार जगहों पर, मजेदार रहेगी छुट्टियां

अगस्त में काफी छुट्टियां मिलने वाली है। ऐसे में आप अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जा सकते हैं। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड और महाराष्ट्र से लेकर केरल की इन शानदार जगहों को डेस्टिनेशन बना सकते हैं।

अगस्त के महीने में भी देशभर के कई हिस्सों में झमाझम बारिश होती रहती है। मानसून के दौरान इन जगहों पर जाने का अलग ही मजा आता है। आप भी अपने चार दोस्तों के साथ घूमने के लिए अलग ही मजा होता है। जब हम कहीं ट्रिप पर दोस्तों के साथ जाते हैं, तो घूमने का अलग ही मजा आता है। आपको इस लेख में बताएंगे कि देश की कुछ शानदार और खूबसूरत जगहों के बारे बताने जा रहे हैं। जहां दोस्तों के साथ आप धमाकेदार अंदाज में छुट्टियां माना सकते हैं।

मसूरी

जब घूमने की बात आती है तो सबसे पहला नाम उत्तराखंड या हिमाचल का आता है। दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए नैनीताल या ऋषिकेश नहीं, बल्कि मसूरी पहुंच जाएं। मसूरी पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। जब यहां बारिश होती है तो खूबसूरती चरम पर होती है। यहां आप रात भर घूम सकते है, होटल में पार्टी कर सकते हैं। मसूरी में आप कंपनी गार्डन, कैम्पटी वॉटरफॉल, मॉल रोड और जॉर्ज हिल्स जैसी खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं।

माउंट आबू

इस बारिश को मौसम में आप राजस्थान के शाही शहरों में घूमने का प्लान बना सकते हैं। माउंट आबू राजस्थान का हिल स्टेशन है। यहां शाम से लेकर रात तक पार्टी कर सकते है। माउंट आबू में आप दोस्तों के साथ निक्की झील, गुरु शिखर, रॉक पॉइंट व्यू और दिलवाड़ा जैन मंदिर जैसी चर्चित जगहों को एक्सप्लोर करें।

गोवा

पार्टी और बीच के लिए गोवा सबसे फेमस है। गोवा में समुद्र किनारे आप दोस्तों के साथ नाइट आउट का शानदार लुत्फ उठा सकते है। नाइट क्लब में आप दोस्तों के साथ पार्टी कर सकते हैं। गोवा में आप नाइट क्लब में पार्टी में कर सकते हैं।

धर्मशाला

हिमाचल प्रदेश की वादियों को मजा लेना है तो आप अगस्त के महीने में घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आप धर्मशाला जाएं। धर्मशाला हिमाचल का सबसे बेहतरीन हिल स्टेशन माना जाता है। यहां आप धमाकेदार पार्टी कर सकते हैं। धर्मशाला में नाइट आउट का प्लान भी कर सकते हैं।

हनीमून फेज के बाद रिश्ते की बुझती लो को कैसे जलाएं

हनीमून चरण के बाद, यह बहुत आम है कि लोग सेक्स करने की इच्छा खोना शुरू कर देते हैं, खासकर अपने पार्टनर के साथ। तो, हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? हम अपने रिश्ते में हनीमून चरण की चिंगारी को कैसे बनाए रख सकते हैं?

हम सभी जानते हैं कि रिश्ते विभिन्न चरणों से गुजरते हैं और ये चरण किसी न किसी तरह से हमारे यौन जीवन को प्रभावित करते हैं। हनीमून चरण के बाद, यह बहुत आम है कि लोग सेक्स करने की इच्छा खोना शुरू कर देते हैं, खासकर अपने पार्टनर के साथ। तो, हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? हम अपने रिश्ते में हनीमून चरण की चिंगारी को कैसे बनाए रख सकते हैं?

ये बहुत ही आम सवाल हैं, जो हर किसी के दिमाग में आते हैं। देखा जाए तो इन सवालों से खुद को घिरे हुए पाना जरुरी है क्योंकि ये अंतरंगता और संबंध बनाए रखने के बारे में एक स्वाभाविक चिंता को दर्शाते हैं। हालाँकि, एक्सपर्ट्स के अनुसार, पूछने के लिए ये सही प्रश्न नहीं हो सकते हैं। इसके बजाय, ऐसे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो यौन ज़रूरतों और इच्छाओं के बारे में, जिनपर लोगों को अपने पार्टनर के साथ चर्चा करने की जरुरत है।

सबसे पहले, यह पता लगाना आवश्यक है कि आप और आपके पार्टनर के लिए अंतरंगता का क्या अर्थ है। अंतरंगता केवल शारीरिक संबंध के बारे में नहीं है, इसमें भावनात्मक निकटता और आपसी समझ भी शामिल है।

रिलेशनशिप थेरेपिस्ट ल्यूसिल शेकलटन ने लिखा, 'इस पोस्ट में, मैं आपको अपने साथी के साथ अपने सेक्सुअल कनेक्शन और एक यौन प्राणी के रूप में खुद के साथ अपने रिश्ते का पता लगाने के लिए कुछ बातें बताने जा रहा हूँ और साथ ही आपको साथ मिलकर कुछ सवाल पूछने के लिए कहूँगा। मैं यह उम्मीद करता हूँ कि यह आपको एक-दूसरे से बात करने के लिए प्रोत्साहित करेगा कि आप क्या अनुभव कर रहे हैं क्योंकि इच्छाओं में अंतर को प्रबंधित करने के लिए संचार महत्वपूर्ण है।'

अपने साथी के साथ अपने यौन संबंध के बारे में खुद से क्या सवाल पूछें?

आपके जीवन के इस मोड़ पर आपके लिए यौन संबंध का क्या मतलब है? क्या आपके लिए अपने रिश्ते में यौन अंतरंगता रखना महत्वपूर्ण है? क्या आप अपने साथी के सामने अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने में सहज महसूस करते हैं? पहल कौन करता है? क्या पहल इस तरह से की जाती है कि यौन संबंध आकर्षक हो? जब यौन संबंध होता है, तो क्या यह आनंददायक होता है? जब आप सोचते हैं कि आप वास्तव में किस तरह का यौन संबंध चाहते हैं, तो यह आपके वर्तमान यौन संबंध से किस तरह अलग होगा? अपने साथी के साथ यौन संबंध से आपको क्या मिलता है जो आपको अकेले यौन संबंध से नहीं मिलता?

अपने साथ अपने रिश्ते के बारे में खुद से ये सवाल करें

आप अपने शरीर में कितना सहज महसूस करते हैं? क्या आप अपने शरीर के बारे में जो महसूस करते हैं, उसका असर आपकी यौन इच्छा पर पड़ता है? आपके शरीर में उत्तेजना होने पर कैसा महसूस होता है? वह भावना किस वजह से होती है? क्या आपको लगता है कि आप बिना किसी निर्णय के अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर सकते हैं? क्या आप अपने साथी के प्रति प्रतिक्रिया में इच्छा महसूस करते हैं? या यह अपने आप होता है? आपके ब्रेक (टर्न-ऑफ) और एक्सीलेटर (टर्न-ऑन) क्या हैं? क्या आप जानते हैं कि आपकी क्षमता (आपका मानसिक और भावनात्मक तनाव) आपको यौन रूप से कैसे प्रभावित करती है?

दिल्ली में कई कोचिंग सेंटर्स एमसीडी की बिल्डिंग बॉयलॉज की उड़ा रहे धज्जियां , सब पर कार्रवाई

सुषमा रानी

नई दिल्ली। राजेंद्र नगर में हुए दुखद हादसे के बाद दिल्ली नगर निगम की मेयर डॉ. शैली ओबेरॉय एक्शन मोड में हैं। मंगलवार को वो खुद जमीन पर उतरीं और प्रीत विहार का दौरा कर नियमों को ताक पर रखकर बेसमेंट में संचालित हो रहे कोचिंग सेंटरो का निरीक्षण किया। इस दौरान मेयर संस्कृति अकादमी का निरीक्षण करने पहुंची तो पाया कि वो बेसमेंट के अंदर संचालित हो रहा है। उन्होंने कोचिंग सेंटर से बेसमेंट में कक्षाएं चलाने की अनुमति के पेपर मांगे तो वो दिखाने में विफल रहा। इसके बाद उनके निर्देश पर एमसीडी के अधिकारियों ने अकादमी को सील क दिया। रविवार से चल रही कार्रवाई के तहत अब तक अवैध रूप से संचालित हो रहे 19 कोचिंग सेंटर को सील किया जा चुका है। मेयर ने कहा कि पूरी दिल्ली में कई सारे कोचिंग सेंटर्स ने एमसीडी की बिल्डिंग बॉयलॉज की धज्जियां उड़ा कर रख दी है। एमसीडी इन सब पर कड़ी कार्रवाई करने जा रही है।

दिल्ली नगर निगम की मेयर डॉ. शैली ओबेरॉय ने

कहा कि राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अवैध रूप से संचालित हो रही लाइब्रेरी में अचानक पानी भरने से तीन बच्चों की जान चली गई। पूरी दिल्ली में ऐसे बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं, जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। इन कोचिंग सेंटर्स ने एमसीडी की बिल्डिंग बॉयलॉज की धज्जियां उड़ा कर रख दी है। अब अवैध रूप से संचालित हो रहे सभी कोचिंग सेंटर्स पर कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। नियमों और बिल्डिंग बॉयलॉज का उल्लंघन कर संचालित हो रहे किसी भी कोचिंग सेंटर को बक्शा नहीं जाएगा। अगर किसी अधिकारी की इसमें मिलीभगत पाई जाएगी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

मेयर ने कहा कि मैंने प्रीत विहार में संस्कृति अकादमी का निरीक्षण किया। यहां बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चल रहा है, जो कि अवैध है। कोचिंग संस्थान ने एमसीडी के नियमों का उल्लंघन किया है। बेसमेंट में कोई कोचिंग सेंटर चलता है तो दो तरफ से प्रवेश और निकास होता है। लेकिन पूरी दिल्ली में बहुत सारे कोचिंग सेंटर ऐसे हैं, जो एक भी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। नियमों का पालन नहीं करने वाले कोचिंग सेंटरों के खिलाफ एमसीडी एक्शन मोड में आ चुकी है। एमसीडी उन सभी कोचिंग सेंटरों को सील करने जा रही है। जिस प्रकार से राजेंद्र नगर में बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है, हमें उसका दुख और अफसोस है। आने वाले समय में कई अवैध कोचिंग सेंटरों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई होगी।

चार दिन से धरना दे रहे छात्र, राव कोचिंग सेंटर के सामने देर रात तक जुटे

दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में छात्रों की मौत के बाद छात्रों का विरोध-प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी है। वह दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को देर रात कोचिंग सेंटर के सामने मोबाइल टॉर्च जलाकर विरोध जताया। छात्र अपनी मांगों को लेकर अभी भी डटे हुए हैं।

नई दिल्ली। ओल्ड राजेंद्र नगर में 27 जुलाई को राव आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में बारिश का पानी भरने से तीन विद्यार्थियों की मौत के बाद छात्रों का प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी है। छात्र अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। छात्रों ने मंगलवार शाम को कोचिंग सेंटर के सामने मोबाइल फोन की टॉर्च जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है। छात्र एक-एक कर सभी को संबोधित कर रहे हैं। कुछ कोचिंग संचालकों ने मौके पर पहुंचकर छात्रों से बात भी की।

मुखर्जी नगर में भी छात्रों का प्रदर्शन : ओल्ड राजेंद्र नगर के साथ सोमवार रात को मुखर्जी नगर में भी प्रदर्शन हुआ था। इसके बाद वहां के भी कोचिंग सेंटर बंद कर दिए गए हैं। छात्रों का कहना है कि एक-एक करोड़ का मुआवजा मृतक छात्रों के स्वजन को दिया जाना चाहिए। जिम्मेदार एमसीडी और अन्य एजेंसियों के अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

मांगें नहीं मानने तक धरना जारी रहेगा : अवैध कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन इनका दोबारा संचालन न हो, इसको भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। एक छात्र संकेत ने कहा, गर्मी और उमस भरे मौसम में सभी डटे हैं और हमारी मांगें जब तक मानी नहीं जाएंगी, धरना जारी रहेगा।

दिल्ली कोचिंग मामले में पुलिस ने सात लोगों को किया गिरफ्तार, अब तक क्या-क्या हुआ?

ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग सेंटर में हुए हादसे में तीन आईएस अभ्यर्थियों की जान चली गई थी। जिसके बाद छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में अभी तक सात लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब अन्य जिम्मेदारों की पहचान करने में पुलिस जुटी है। विस्तृत जांच के लिए मुकदमा क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर किया जा सकता है।

नई दिल्ली। ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग सेंटर राव आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में वर्षा का पानी भरने से डूबकर तीन विद्यार्थियों की मौत के मामले में सात लोगों की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस अब सिविक एजेंसियों व अन्य जिम्मेदारों का पता लगाने में जुट गई है।

इस हादसे के लिए दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। जिनकी जिम्मेदारी उस इलाके के सीवर व नालों की साफ सफाई से लेकर बिल्डिंग में चलने वाली गतिविधियों पर नजर रखने की थी, इलाके के फायर विभाग के अधिकारी, जिसने कोचिंग सेंटर मालिक को एनओसी दी थी और बीट अफसर जिन पर इलाके में चलने वाली हर दिन की गतिविधियों पर नजर रखने की जिम्मेदारी थी।

दिल्ली पुलिस ने अब तक इन लोगों को किया गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने अब तक बिल्डिंग मालिक, कोचिंग सेंटर मालिक, कोआर्डिनेटर व सड़क पर जलभराव के दौरान गुजरने वाले एसयूवी चालक को गिरफ्तार किया है। हालांकि मामला राजनीतिक रूप लेने व चौतरफा विरोध के कारण दिल्ली पुलिस अब प्रशासनिक लापरवाही में शामिल जिम्मेदारों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास का दावा कर रही है।

पुलिस अपने दावे पर कहां तक सफल हो पाएगी यह कहना मुश्किल है। क्योंकि करीब ढाई माह पहले विवेक विहार स्थित बेबी केयर सेंटर में आग लगने से सात शिशुओं की मौत के मामले में भी पुलिस जांच में स्वास्थ्य निदेशालय की लापरवाही से घटना घटने का पता चला था। पुलिस ने आरोप पत्र में भी इस बात का जिक्र किया है कि स्वास्थ्य निदेशालय से पांच बेड की अनुमति दी थी, लेकिन घटना के समय 12 बेड का अस्पताल चल रहा था।

उपराज्यपाल ने पुलिस आयुक्त को दिए जांच के निर्देश

नौ मीटर से कम ऊंचाई होने के कारण बिल्डिंग मालिक को फायर से एनओसी की जरूरत नहीं थी। जिससे अस्पताल के मानक के अनुरूप अस्पताल मालिक ने आग बुझाने के यंत्र आदि का बंदोबस्त

नहीं किया था। मामले में अस्पताल मालिक व डॉक्टरों को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जिस स्वास्थ्य निदेशालय पर अस्पताल को चेक करने की जिम्मेदारी थी उसके किसी को भी अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।

सोमवार को ओल्ड राजेंद्र नगर में मौके का मुआयना करने व विद्यार्थियों से बातचीत के बाद उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा व विशेष आयुक्त कानून एवं व्यवस्था रवींद्र सिंह यादव को राज निवास बुलाकर उनसे घटना को लेकर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जांच की रूपरेखा के बारे में निर्देश दिए।

दोनों विभागों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

राव कोचिंग सेंटर हादसे के मामले में पुलिस का कहना है कि नगर निगम ने मेंटेनेंस विभाग में अनुबंध पर तैनात जिस कनिष्ठ अभियंता विनय मित्तल और वर्क्स विभाग के सहायक अभियंता विश्राम मीणा को निलंबित कर दिया है, उन्हें मुकदमे में आरोपित बना गिरफ्तार किया जाए अथवा नहीं इसको लेकर विचार किया जा रहा है।

दिल्ली फायर विभाग के अधिकारी ने बेसमेंट में स्टोर के लिए एनओसी दी थी। फायर विभाग के अधिकारी की भूमिका के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। इन दोनों विभागों को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा गया है। जवाब मिलने के बाद निर्णय लिया जाएगा। मुख्यालय सूत्रों की मानें तो मामले की विस्तृत जांच के लिए केस को क्राइम ब्रांच में भी ट्रांसफर किया जा सकता है।

दिल्ली पुलिस करोल बाग, ओल्ड राजेंद्र नगर व पटेल नगर में स्थित उन सभी बिल्डिंग की सूची तैयार कर रही है, जिसमें बेसमेंट में कोचिंग सेंटर मालिकों ने अवैध रूप से लाइब्रेरी बना रखी है। कुछ को स्टोर बनाने व कुछ को पार्किंग करने की शर्त पर एनओसी दी गई है, लेकिन बेसमेंट में अवैध रूप से अन्य व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं।

सभी बीट अफसरों को सूची बनाने की जिम्मेदारी दी गई हैं। उक्त सूची तैयार करके पुलिस एसडीएम व निगम के अधिकारी को कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखेगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक राव कोचिंग सेंटर के चेयरमैन वीपी गुप्ता हैं। मामले में गिरफ्तार किए गए कोचिंग सेंटर के सीईओ अभिषेक गुप्ता उनका दामाद है। जिनके जिम्मे कोचिंग सेंटर के संचालन की जिम्मेदारी थी।

कोचिंग सेंटर का शेयर वीपी गुप्ता की बेटी के नाम पर है। पुलिस इनकी जिम्मेदारी के बारे में भी जांच कर रही है। कानूनी राय ले रही है कि इन्हें आरोपित बनाया जाए अथवा नहीं। पुलिस अधिकारी का कहना है कि शनिवार की रात राव कोचिंग सेंटर में पानी भरने से फायर, एनडीआरएफ व पुलिसकर्मियों ने रेस्क्यू कर जिन 15 विद्यार्थियों को बाहर निकाला था। उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। इनके बयान से घटना की सच्चाई का पता लग सकेगा, जिससे आगे की कार्रवाई में मदद मिलेगी।

दिल्ली सरकार की लूट यह लूट नहीं डाका है

बिजली दरों में वृद्धि के कारण

ध्यान से पढ़ना और पूरा पढ़ना

बिजली कंपनी के द्वारा बिजली की कीमतों में प्रति यूनिट पैसे बढ़ा कर अपने घाटे को उपभोक्ता से वसूल करती है। दिल्ली सरकार ने बिजली की कीमतों में रेट इसलिए नहीं बढ़ाने दिए कि जनता को पता चल जाएगा। इसलिए PPAC Tax में वृद्धि कर दी जिससे बिजली की कीमतों में प्रति यूनिट 35.6% की वृद्धि कर दी गई।

PPAC क्या है? पावर, परचेज, एडजेस्टमेंट, कांस्ट, दिल्ली में बिजली की मांग बढ़ती है तो बिजली कंपनी दूसरे राज्यों से मंहगे रेट से बिजली खरीदती है इसे PPAC कहते हैं।

मेरा आप से अनुरोध है बिजली के बिलों को ध्यान से देखो। दिल्ली सरकार ने कुल 55.83% तक Tax (कर) लगा रखा हैं। जो इस प्रकार से जनता से वसूले जा रहे है।

(PPAC 35.6%+Electric Charge 8% + Elect TA 5% + Pension Tax 7%, Fixed Charge पर PPAC भी अलग से लगता है।)

उदाहरण के लिए अगर किसी उपभोक्ता का 2000 प्रति महीने का बिल आ रहा है। तो उसमें लगभग 1100 रू0 टैक्स लगा हुआ है। उपभोक्ता का वास्तविक बिल 900 रू0 प्रति महीने है।

7% Pension Tax क्या है?

जो BSES के कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं और उनकी जो पेंशन दी जाती है, वह दिल्ली की भोली भाली जनता से टैक्स के रूप में ली जाती है जबकि यह राशि दिल्ली सरकार को अपने बजट से कर्मचारियों को देनी चाहिए।

दिल्ली में बिजली की माँग 3 महीने बढ़ती है, लेकिन PPAC पूरे वर्ष लगाया जाता है?

आप मेरी बात से सहमत है? तो इसका विरोध करें।

ओल्ड राजेंद्र नगर में हादसा होने के MCD ने गिनाए कारण

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली नगर निगम ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। निगम ने पांच पेज की अपनी रिपोर्ट में घटना का सिलसिले वार तरीके से जिक्र किया है। वहीं मध्य दिल्ली के जिलाधिकारी ने भी अपनी रिपोर्ट मंडलायुक्त को सौंप दी है लेकिन लेकिन विस्तृत जांच के लिए समय मांगा है। एमसीडी ने हादसे का एक कारण कार के गुजरने को भी बताया है।

नई दिल्ली। ओल्ड राजेंद्र नगर की कोचिंग सेंटर राव आईएएस स्टडी सर्किल में तीन छात्रों की मौत पर दिल्ली नगर निगम और मध्य दिल्ली के जिलाधिकारी ने अपनी रिपोर्ट मंडलायुक्त को सौंप दी है। रिपोर्ट ने निगम ने कहा है कि सड़क पर जलभराव था और वहां से तेज रफ्तार गाड़ी गुजरी तो पानी हिलोरे के साथ इमारत की ओर बढ़ गया।

इमारत में कोई सुरक्षाकर्मी और निगरानी न होने की वजह से इमारत के भूतल पर घुसा और बिना अवरूद्ध तरीके से पानी बेसमेंट तक पहुंचा। इमारत निचले इलाके में भी थी। बावजूद इसका कोई अतिरिक्त इंतजाम बेसमेंट से पानी निकालने के लिए नहीं किया गया था।

नाले पर कर रखा है अतिक्रमण

इतना ही नहीं स्लैब द्वारा इलाके में व्यावसायिक संस्थानों ने नाले पर कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से नाले की सफाई अवरूद्ध होती है।

अन्य विभागों ने क्या किया

एमसीडी ने अपनी रिपोर्ट में दो अभियंताओं पर कार्रवाई और एक को कारण बताओं नोटिस देने की बात इस मामले में बताई है। जबकि मध्य जिले के जिला मजिस्ट्रेट ने घटना का विवरण तो दे दिया है, लेकिन विस्तृत जांच के लिए समय मांगा है।

इस पर मंडलायुक्त ने उन्हें सात दिनों का समय देते हुए जांच पूरी करने को कहा है। एमसीडी की रिपोर्ट में बताया गया है कि रात साढ़े आठ बजे से सुबह साढ़े सात बजे तक घटना पर पानी निकाला गया था।

निगम ने अपनी रिपोर्ट में बताए घटना के प्रमुख कारण।

कोई सुरक्षाकर्मी और निगरानी न होने की वजह से घुस गया था इमारत में पानी।

200 फुट इलाके में जलभराव होने और तेज रफ्तार में गाड़ी गुजरने से पानी को मिल गया था कोचिंग सेंटर में बहाव का रास्ता।

कोचिंग सेंटर के सामने वाले ड्रेनेज पर टाइल व पत्थरों से कब्जा कर लिया गया था, जिसकी वजह से नाले की सफाई संभव नहीं थी।

कोचिंग सेंटर ने निचले इलाके में होने और सड़क पर पानी जमा होने के बाद भी जल निकासी की व्यवस्था को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया था। साथ ही इस तरह की घटना से निपटने के लिए कोई अतिरिक्त उपाय नहीं कर रखे थे।

इलाके में व्यावसायिक संपत्तियां होने की वजह से सभी ने जल निकासी व्यवस्था को अवरूद्ध कर रखा है।

हिंदुस्तानी भाषा अकादमी का "दोहा विधा" पर तृतीय काव्य प्रतिभा सम्मान का आयोजन

परिवहन विशेष न्यूज

एसडी सेठी। दिल्ली। भारतीय भाषाओ के प्रचार-प्रसार और संवर्धन के लिए समर्पित हिंदुस्तानी भाषा अकादमी की ओर से तृतीय काव्य प्रतिभा सम्मान सम्मान समारोह का आयोजन करने जा रहा है। इसके तहत साहित्य की ₹दोहा विधा₹ को केन्द्र में रखकर उसको आगे बढाने के तहत चयनित दोहों का एक साझा संग्रह भी प्रकाशित किया जाएगा। इस बावत अकादमी के अध्यक्ष सुधाकर पाठक ने मीडिया को बताया कि , ₹दोहा विधा₹---- ₹प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए पूर्णतः निशुल्क पंजीकरण है। जिसमें कोई पंजीकरण शुल्क ,प्रकाशन शुल्क, एवं किसी किस्म की सदस्यता शुल्क नहीं लिया जायगा। यह पूर्णतः फ्री है। (1) इस योजना में सम्मिलित होने के लिए कोई शुल्क नहीं है।(2) भाग लेने वाले इच्छुक रचनाकारो से उनके द्वारा मौलिक स्वरचित 15 दोहे, संक्षिप्त परिचय, और एक पासपोर्ट फोटो अनिवार्य है।(3) इस योजना के तहत प्राप्त प्रविष्टियों में से केवल 50 श्रेष्ठ दोहाकारो का चयन निर्णायक मंडल द्वारा किया जाएगा।(4) चयनित सर्वश्रेष्ठ दोहाकारों को एक भव्य समारोह में 5100/-रूपये नगद राशि ,सम्मान- पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया जाएगा।वहीं समारोह के मौके पर सांझा दोहा संग्रह पुस्तक का लोकार्पण भी किया जाएगा। जिसकी एक-एक प्रति सभी रचनाकार को भेंट की जाएगी। संस्था के अध्यक्ष सुधाकर पाठक के मुताबिक 15 अगस्त,2024 तक सभी प्रतिभागी अपनी मौलिक रचना (यूनिकोड फॉण्ट, वर्ड फाइल के रूप में अकादमी की अधिकृत मेल :- hindustanibhashaakadmi@gmail.com पर भेजने की कृपा करें। श्री पाठक ने बताया कि अकादमी ने इससे पहले प्रथम, द्वितीय काव्य प्रतिभा सम्मान के तहत क्रमशः ₹गीत तथा ₹गजल₹ विधा पर प्रतियोगिता का आयोजन कर चुके है।

नरेला के स्मृति वन में "एक पेड मां के नाम, शुद्ध वायु-बढाए आयु" की थीम का आयोजन

परिवहन विशेष।एसडी सेठी

नरेला में डीडीए के स्मृति वन में वन महोत्सव के तहत एक पेड मां के नाम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) हॉरटिकल्चर विभाग के डिवीजन-10 के अनुभाग अधिकारी राघव मौर्य, मुरलीधर मीणा, डिप्टी डायरेक्टर डीडीए हॉल्टीकल्चर एवं सुरेंद्र चौहान सहायक निदेशक के सानिध्य में आयोजित किया गया। इस मौके पर नागरिक अधिकार आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष- राजव्रत आर्य को भी विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया। स्मृति वन में सैंकडो की संख्या में फल-एवं छायादार पेड लगाए गए। इस विशाल पार्क में रोजाना आने वाले यूजर्स ने भी डीडीए का सहयोग कर एक पेड मां के नाम, के तहत छायादार पेडों को लगाया। समारोह में क्षेत्रीय गणमान्य लोगों में कर्मवीर गौड, रवि खत्री, संजय, अशोक खत्री, नरेश, वीरेंद्र गर्ग, रवि तुषीर, सुनील खत्री, संजय- राजेश- दहिया, राजेश गर्ग, विकास कुमार, संतोष मुंशी, विनोद जयसवाल, कैलाश कुमार, एवं वीरेंद्र कुमार भी उपस्थित थे। इस अवसर पर संबोधित करते हुए नागरिक अधिकार आंदोलन के अध्यक्ष राजव्रत आर्य ने "शुद्ध वायु-बढाये आयु" का नारा देते हुए चेताया कि देश में पैर पसारते प्रदूषण से मुक्ती पाने के लिए कंक्रीट के जंगल से लडाई लडनी पडेगी। इसका एक मात्र कारगर हथियार पेड-पौधों का रोपण है। वहीं डीडीए के राघव मौर्य ने कहा कि इस प्रदूषण की लडाई में पेड पौधो की फौज को तैयार करने में सभी के सहयोग की जरूरत है। जैसे आज के एक पेड मां के नाम के तहत एक जन आंदोलन खडा करना है।

"अंगदान जन जागरूकता अभियान" का हुआ समापन

स्वतंत्र सिंह भुल्लर

नई दिल्ली। अंगदान एवं प्रत्यारोपण समन्वय समिति (ODTCC) ने अंगदान जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रमों के साथ महीने भर चलने वाले "अगदान जन जागरूकता अभियान₹ (जन जागरूकता अभियान) का सफलतापूर्वक समापन किया।

अभियान की मुख्य विशेषताएं:

विशेष सम्मान समारोह में चिकित्सा अधीक्षक द्वारा दाता परिवारों को सम्मानित किया गया। विभिन्न प्रत्यारोपण प्रक्रियाओं पर शैक्षिक सत्र आयोजित किए गए: अस्थि प्रत्यारोपण, गुर्दे का प्रत्यारोपण, कॉर्निया प्रत्यारोपण, हृदय प्रत्यारोपण, त्वचा बैंक। जागरूकता बढ़ाने के लिए MBBS छात्रों ने ₹नुक्कड़ नाटक₹ (स्ट्रीट प्ले) का प्रदर्शन किया। निवासियों, छात्रों, नर्सों, कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों ने सूचनात्मक सत्रों में भाग लिया। अंगदान के बारे में जानकारी को परखने और उसे बेहतर बनाने के लिए एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अंतिम दिन, विभिन्न कार्यक्रमों के निर्णायकों, विजेताओं और प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। इस अभियान ने सफलतापूर्वक चिकित्सा पेशेवरों, छात्रों और आम जनता को शामिल किया, जिससे अंगदान और इसकी जीवन-रक्षक क्षमता के बारे में अधिक समझ विकसित हुई। चिकित्सा अधीक्षक डॉ. वंदना तलवार ने सफल आयोजन के लिए ओडीटीसीसी टीम को बधाई दी। इस पहल ने अंगदान के महत्व के बारे में लोगों की समझ को काफी बढ़ाया है। समापन समारोह में हमारी टीम की कड़ी मेहनत और समुदाय से मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया का जश्न मनाया गया। हमें उम्मीद है कि इस अभियान से अंगदान की प्रतिज्ञाओं में वृद्धि होगी और भविष्य में कई लोगों की जान बचेगी। उन्होंने पिछले छह महीनों में 4 शव दान के सफल समापन के बारे में भी बताया, जिससे कई प्राप्तकर्ताओं को लाभ हुआ। डॉ. वंदना चक्रवर्ती ने कहा, ₹अंगदान एवं प्रत्यारोपण समन्वय समिति की प्रभारी के रूप में, मुझे हमारे अंगदान जन जागृति अभियान के प्रभाव पर गर्व है। इस अभियान के माध्यम से, हमने अनगिनत व्यक्तियों को अंगदान की जीवन-रक्षक क्षमता के बारे में शिक्षित किया है। हमने पूछताछ और प्रतिज्ञाओं में उत्साहजनक वृद्धि देखी है। हमारा काम यहीं नहीं रुकता - हम अपने समुदाय में अंगदान की एक मजबूत संस्कृति बनाने के लिए इस गति को बनाए रखना जारी रखेंगे।" ओडीटीसीसी निरंतर शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से अंगदान को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

नोएडा एयरपोर्ट के पास खरीदें प्लॉट, YEIDA ने दिया घर बनाने का मौका; अब तक 28 हजार से अधिक आवेदन

YEIDA रेजिडेंशियल प्लाट स्कीम यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) ने नोएडा एयरपोर्ट के पास अपनी आवासीय भूखंड योजना शुरू की है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। YEIDA के सीईओ ने बताया कि योजना में दस फीसदी पंजीकरण राशि के साथ ही 28867 आवेदन भरे जा चुके हैं। इस लेख के माध्यम से पढ़ें खबर से संबंधित बाकी अपडेट।

ग्रेटर नोएडा। (YEIDA रेजिडेंशियल प्लाट स्कीम) यमुना प्राधिकरण की आवासीय भूखंड योजना समाप्त एक सप्ताह का समय बचा है। योजना में अब तक 28867 आवेदन आ चुके हैं। वहीं 74939 लोगों ने योजना में आवेदन के लिए पंजीकृत किया है। प्राधिकरण को उम्मीद है कि योजना समाप्त होने तक आवेदकों की संख्या काफी बढ़ जाएगी।

यमुना प्राधिकरण ने चालू वित्त वर्ष में पहली आवासीय भूखंड योजना पांच जुलाई को निकाली थी। इस योजना में कुल 361 भूखंड हैं। इसमें सामान्य श्रेणी के लिए 280 भूखंड हैं। प्राधिकरण सीईओ ने बताया कि योजना में दस प्रतिशत पंजीकरण राशि के साथ रविवार तक 28867 आवेदन भरे जा चुके हैं। 74939 आवेदकों ने पंजीकरण कर ब्रोशर खरीदा है।

सबसे अधिक आवेदन 120 वर्गमीटर श्रेणी में

योजना में सबसे अधिक आवेदन 120 वर्गमीटर श्रेणी में हुए हैं। इसमें 11606 आवेदन हुए हैं। वहीं 162 वर्गमीटर श्रेणी में 7784, 200 वर्गमीटर श्रेणी में 387, 300 वर्गमीटर श्रेणी में 10253, पांच सौ वर्गमीटर श्रेणी में 1432, एक हजार वर्गमीटर श्रेणी में 454 व चार हजार वर्गमीटर श्रेणी में 123 आवेदन हुए हैं।

लॉटरी से होगा ड्रा

आवासीय भूखंड योजना में आवेदन करने वालों की किस्मत का फैसला 20 सितंबर को होगा। योजना में मिले आवेदकों के नाम की पर्ची निकाल कर भूखंड का आवंटन किया जाएगा।

सबसे पहले विकल्प एक चुनने वालों को मौका मिलेगा ।इसके सापेक्ष भूखंडों की संख्या अधिक होने पर विकल्प दो और तीन के आवेदकों को ड्रा में शामिल होने का मौका मिलेगा।

बढ़ सकती है भूखंडों की संख्या

आवासीय भूखंड योजना में भूखंडों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। यमुना प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश रेरा में करीब 500 भूखंड का प्रस्ताव पंजीकरण के लिए भेजा है।

अगर रेरा इस भूखंड योजना समाप्त होने से पहले स्वीकृति प्रदान कर देता है तो इन भूखंडों को मौजूदा योजना में शामिल कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आवेदन की तिथि में भी वृद्धि की जाएगी, ताकि अधिक से अधिक लोग योजना का लाभ उठा सके।

दिल्ली के कालिंदी कुंज से नोएडा आने वाले सावधान, डायवर्जन के चलते लग रहा है भीषण जाम

परिवहन विशेष न्यूज

ट्रैफिक पुलिस की ओर से स्थिति को सुधारने के लिए अतिरिक्त ट्रैफिक कर्मियों की तैनाती की गई है। यातायात को नियंत्रित करने और वैकल्पिक मार्गों की जानकारी देने के लिए संकेतक बोर्ड भी लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा लोगों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। जिससे जाम की स्थिति से बचा जा सके।

नोएडा। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर लागू ट्रैफिक डायवर्जन लागू होने से दिल्ली के कालिंदी कुंज से नोएडा आने वालों ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। कल सोमवार सुबह व्यस्त समय में कालिंदी कुंज दिल्ली पुल से ओखला बर्ड सेंचुरी तक ट्रैफिक जाम ने लोगों को मुश्किल में डाल दिया। सुबह और शाम को व्यस्त समय में इस क्षेत्र में वाहनों की लंबी कतारें देखी गईं।

जाम में फंसने के कारण लोगों का धैर्य जवाब दे गया। लोगों ने ट्रैफिक पुलिस से इसकी शिकायत की। कांवड़ियों का जत्था बढ़ने के कारण पिछले शुक्रवार से कालिंदी कुंज दिल्ली से नोएडा आने वाले पुल के एक हिस्से को बंद किया गया है।

वाहनों के लिए बंद है पुल का एक हिस्सा

वाहन चालकों को निकलने के लिए सिर्फ पुल का एक हिस्सा मिल रहा है। पुल पर दो लेन होने में वाहन चलते हैं। दिल्ली कालिंदी कुंज, फरीदाबाद, ओखला से बड़ी संख्या में सुबह और शाम को लोग फैक्ट्री, कंपनी में काम करने के आवागमन करते हैं। इससे यहां सुबह और शाम व्यस्त समय में ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है।

अभी सेक्टर-95 फर्नीचर मार्केट के पास निर्माण कार्य के चलते सेक्टर-16 फिल्म सिटी की ओर जाने वाला मार्ग बंद है। वाहन चालकों को सेक्टर-37, बोटेनिकल गार्डन, सेक्टर-18 होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाना पड़ रहा है।

डायवर्जन के कारण चिल्ला रेड लाइट से पक्षी विहार गेट तक मार्ग पर वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित है। सेक्टर-14ए शनि मंदिर से ओखला बर्ड सेंचुरी होते हुए सिर्फ कांवड़ ले जाने वाले और शिविर लगाने से संबंधित लोगों को छूट है।

ऑफिस जाने वालों को हो रही देरी

वहीं कालिंदी कुंज के पास जाम लगने से कई यात्रियों ने शिकायत की कि उन्हें रोजाना अपने कार्यालय या घर पहुंचने में अत्यधिक समय लग रहा है। विकास वर्मा ने कहा, कि उन्हें अपने ऑफिस पहुंचने में सामान्यतः 30 मिनट लगते हैं, लेकिन डायवर्जन के कारण डेढ़ घंटे से भी ज्यादा समय लगता है। ट्रैफिक जाम के कारण रोज की दिनचर्या प्रभावित होती है।

पुलिस कमिश्नर ने कांवड़ियों का जाना कुशलक्षेम

पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्ध नगर लक्ष्मी सिंह ने सोमवार को डीएनडी स्थित शिव मंदिर पहुंच कांवड़ियों का कुशलक्षेम जाना। पुलिस अधिकारियों को कांवड़ शिविरों में व्यवस्था दुरुस्त रखने और यातायात को लेकर भी विशेष सावधानी बरतने पर जोर दिया।

शहर से होकर गुजरने वाले कांवड़ियों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई है। पुलिस प्रशासनिक अधिकारी कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से कराने में जुटे हैं।

कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने मार्गों का निरीक्षण किया। यात्रा सकुशल संपन्न करने को कांवड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया। कमिश्नर ने सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था को भी परखा।

शिविरों में नियुक्त चिकित्सक टीम से वार्ता कर शिव भक्तों की देखरेख करने को निर्देशित किया। पुलिस कर्मियों को कांवड़ यात्रा को लेकर पीसीआर, पीआरवी वाहनों से लगातार पेट्रोलिंग करने पर जोर दिया।

मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बन महिला से की ठगी, मनी लॉन्ड्रिंग का भय दिखाकर लिया था झांसे में

परिवहन विशेष न्यूज

हरियाणा के गुरुग्राम में मनी लॉन्ड्रिंग का भय दिखा पुलिस अधिकारी बन एक महिला से ठगी कर ली गई। साइबर ठग ने महिला को स्काइप पर वीडियो कॉल कर जांच के नाम पर अरेस्ट किया था। जिससे महिला घबरा गई थी और ठगे के झांसे में आ गई। इसके अलावा ठगी के और भी कई मामले प्रकाश में आए हैं।

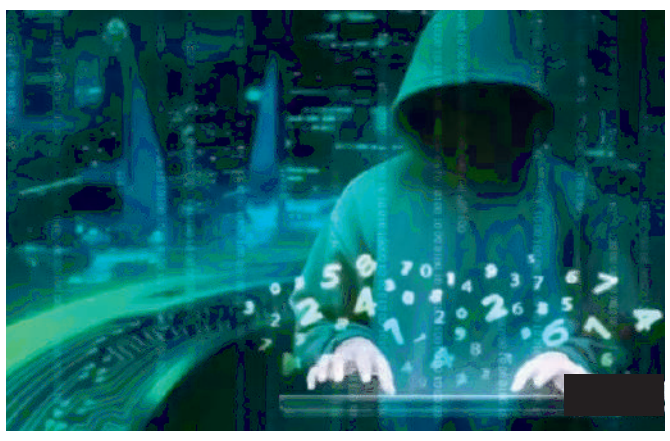

गुरुग्राम। साइबर क्राइम साइबर ठगों ने एक बार फिर मनी लॉन्ड्रिंग का भय दिखाकर मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी के नाम से गुरुग्राम की महिला को झांसे में लिया और धोखाधड़ी की। महिला ने साइबर थाना दक्षिण में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है।

सोहना की सिग्नेचर ग्लोबल सेरेनाज सोसायटी निवासी नगमा ने थाना पुलिस को दी शिकायत में कहा कि उनके पास 23 जुलाई को फीडेक्स कूरियर कंपनी की तरफ से फोन आया। फोन करने वाले ने कहा कि उनके नाम से एक कूरियर बुक है और यह ताइवान जा रहा है। इसमें अवैध चीजें हैं। इसलिए वह उनका फोन मुंबई क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर कर रहे हैं।

वीडियो कॉल के माध्यम से किया था अरेस्ट

इसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच के डीसीपी बनकर साइबर ठग ने महिला को झांसे में लिया और कहा कि उनके आधार कार्ड और नंबर का इस्तेमाल मनी लांड्रिंग में किया जा रहा है। महिला को स्काइप पर वीडियो कॉल के माध्यम से अरेस्ट किया गया। जांच में सहयोग करने और किसी को न बताने की धमकी दी गई।

इस दौरान खातों की जांच और फिर एनओसी देने के नाम पर उनसे दो खातों में 47 हजार रुपये ट्रांसफर कराए गए। उनसे यह भी कहा गया कि जांच में सहयोग करने पर उन्हें राशि वापस कर दी जाएगी। रुपये देने के बाद जब उन्होंने दोबारा फोन किया तो किसी ने फोन नहीं उठाया। इस पर उन्हें धोखाधड़ी का अहसास हुआ। साइबर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के नाम पर ठगी

साइबर ठगों ने गुरुग्राम के एक युवक से क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर उससे धोखाधड़ी की। कादरपुर निवासी विजय पवार ने साइबर थाना पुलिस को बताया कि बीते दिनों उनके पास बैंक प्रतिनिधि बनकर किसी ने मैसेज भेजा।

कहा गया कि वह लिंक में कार्ड की डिटेल भरकर लिमिट बढ़ा सकते हैं। इसके बाद उनके कार्ड से कई बार में हजारों रुपये की ट्रांजेक्शन की गई। इसके बाद उन्होंने बैंक में फोन कर कार्ड को ब्लाक करा दिया। उन्होंने कहा कि उनके कार्ड की लिमिट 74 हजार रुपये थी।

पार्ट टाइम जॉब के नाम पर 55 हजार ठगे

साइबर ठगों ने सेक्टर 36ए निवासी एक युवक से पार्ट टाइम जाब के नाम पर 55 हजार रुपये की ठगी कर ली। एवीएल सोसायटी निवासी अमित कुमार ने थाना पुलिस को बताया कि उनके पास कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पर मैसेज आया था। इसमें पार्ट टाइम जॉब कर रुपये कमाने के बारे में बताया गया।

इसके बाद उन्हें टेलीग्राम पर एक ग्रुप से जोड़ दिया गया। यहां उनसे कई टास्क कराए गए और उनके प्रॉफिट दिखाया गया। जब उन्होंने रुपये निकालने चाहे तो उनसे एक बैंक खाते में और टास्क के नाम पर 55 हजार रुपये जमा कराए गए। इसके बाद भी जब रुपये नहीं निकल सके तो उन्हें धोखाधड़ी का अहसास हुआ।

सीएम ग्रिड योजना: ट्रांस हिंडन की आठ सड़कों को चमकाने की तैयारी में जुटा निगम

परिवहन विशेष न्यूज

सीएम ग्रिड योजना के तहत गाजियाबाद जिले में नगर निगम दूसरे चरण में ट्रांस हिंडन की आठ सड़कों को चमकाने की योजना पर काम शुरू किया है। इस योजना पर करीब 161 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं। सभी सड़कों को बनाने से पहले ड्रोन से सर्वे किया जा चुका है। लोगों के बैठने के अलावा पार्किंग और फुटपाथ भी बनाए जायेंगे। जो काफी आकर्षक होंगे।

गाजियाबाद। (सीएम ग्रिड योजना हिंदी समाचार) सीएम ग्रिड योजना के तहत दूसरे चरण में नगर निगम ने ट्रांस हिंडन की आठ सड़कों को चमकाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। ट्रांस हिंडन की आठ सड़कों को चिह्नित कर लिया गया है। सीएम ग्रिड योजना के लिए सड़कों का चयन करने वाली स्थानीय कमेटी ने इस पर फाइनल मुहर लगा दी है। इस पर करीब 161 करोड़ रुपये खर्च किए जाने प्रस्तावित हैं।

वैशाली सेक्टर-चार शॉपिक्स मॉल के पास दो सड़क चिन्हित

निगम के मुख्य अभियंता एनके चौधरी ने बताया कि डाबर तिराहे से कौशांबी बस अड्डे को जाने वाले मार्ग के साथ कौशांबी होते हुए ईडीएम माल के पास गाजीपुर बॉर्डर पर निकलने वाली सड़क के साथ वैशाली सेक्टर-चार शॉपिक्स मॉल के सामने वाली सड़क और वैशाली से रामप्रस्था ग्रीन सोसायटी की तरफ वाली वाली दो सड़कों को चिह्नित किया गया है।

इसके अलावा इंदिरापुरम में काला पत्थर रोड, गौड ग्रीन एवेन्यू को जाने वाली सड़क, ज्ञानखंड और न्यायखंड के बीच से अभिखंड होते हुए साईं मंदिर को जाने वाल सड़क। साथ ही काला पत्थर रोड से सीआईएसएफ की तरफ जाने वाली दो सड़कों को सीएम ग्रिड योजना के तहत दूसरे चरण में विकसित करने के लिए चिह्नित किया गया है।

सड़क के दोनों तरफ फुटपाथ बनाकर लगवाई जाएंगी लाइटें

इन सभी सड़कों का ड्रोन सर्वे भी कराया जा चुका है। इन सड़कों पर लगे बिजली के खंभों व सड़क के ऊपर से गुजर रहे तारों को हटवाकर अंडग्राउंड कराया जाएगा। जहां जरूरत होगी, वहां साइकिल ट्रैक बनाया जाएगा। सड़क के दोनों तरफ फुटपाथ बनाकर लाइटें लगवाई जाएंगी, जिससे फुटपाथ काफी आकर्षक होगा।

महाराष्ट्र के राजभवन में 'तमिलनाडु के मोदी'

उमेश चतुर्वेदी

1998 और 1999 के आम चुनावों में बीजेपी उम्मीदवार के रूप में तमिलनाडु की कोयंबटूर सीट से लोकसभा पहुंच चुके सीपी राधाकृष्णन को दक्षिण भारतीय जहां सीपी के नाम से जानते हैं, वहीं उत्तर भारत में अब वे राधा जी के नाम से भी जाने जाते हैं।

राजनीति के केंद्र में स्थापित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व विराट होकर उभरा है, इसके साथ यह भी सच है कि उनकी खास पहचान उनकी दाढ़ी है। साल 2013 में जब बीजेपी ने मोदी को प्रधानमंत्री पद का अपनी ओर से दावेदार बनाया था, उन्हीं दिनों एक तमिल टीवी पर चर्चा में तमिलनाडु के बीजेपी का एक चेहरा भी शामिल हुआ था। उस नेता ने अपनी पार्टी का दमदार तरीके से पक्ष रखा। उसका कार्यक्रम का ऐसा प्रभाव रहा कि उन्हें दर्शकों ने तमिलनाडु के मोदी के रूप में पुकारना शुरू कर दिया। तमिलनाडु के वही मोदी अब महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। जी हां, आपने ठीक समझा, तमिलनाडु के लोग सी पी राधाकृष्णन को तमिलनाडु के मोदी के रूप में भी जानते हैं। 1998 और 1999 के आम चुनावों में बीजेपी उम्मीदवार के रूप में तमिलनाडु की कोयंबटूर सीट से लोकसभा पहुंच चुके सीपी राधाकृष्णन को दक्षिण भारतीय जहां सीपी के नाम से जानते हैं, वहीं उत्तर भारत में अब वे राधा जी के नाम से भी जाने जाते हैं। शुद्ध शाकाहारी और पूजा-पाठ में श्रद्धा रखने वाले सीपी राधाकृष्णन को पहली बार महत्वपूर्ण राजकीय पद साल 2023 में मिला, जब उन्हें मोदी सरकार ने झारखंड का राज्यपाल मनोनीत किया। 12 फरवरी 2023 का दिन उनके लिए खुशी और निराशा, दोनों का मौका बनकर आया। जब मोदी सरकार ने उन्हें खनिज और प्राकृतिक संपदा से भरपूर झारखंड राज्य का राज्यपाल का दायित्व मिलना मामूली बात नहीं, लेकिन 66 साल की उम्र राजनीति में बहुत ज्यादा नहीं मानी जाती। सीपी इस बात से किंचित निराश थे कि अब उन्हें सक्रिय राजनीति से दूर होना पड़ेगा। वैसे सीपी की दिली चाहत सक्रिय राजनीति में रहते हुए महत्वपूर्ण राजनीतिक दायित्व को निभाना रहा है।

सीपी राधाकृष्णन की बीजेपी की राजनीति में क्या अहमियत है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते आम चुनावों से ठीक पहले जब तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सोंदरराजन ने इस्तीफा देकर चेन्नई से चुनाव लड़ने का फैसला किया तो तेलंगाना के राज्यपाल का प्रभार सीपी को ही मिला। इतना ही नहीं, उन्हें पुदुचेरी के उपराज्यपाल की भी जिम्मेदारी दी गई। एक साथ तीन-तीन राज्यों के राज्यपाल की जिम्मेदारी बहुत कितने लोगों को मिल पाई है?

सीपी राधाकृष्णन का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ, जहां कांग्रेस का बोलबाला था। उनके चाचा कोयंबटूर से कांग्रेस के लोकसभा सदस्य रहे। सीपी बताते हैं कि पहली बार वे दिल्ली अपने चाचा के पास ही आए थे और उनके घर पर रहकर ही दिल्ली देखी थी। चार मई 1957 को तमिलनाडु के त्रिपुर में जन्मे राधाकृष्णन कांग्रेसी पारिवारिक पृष्ठभूमि होने के बावजूद कांग्रेस की बजाय समाजवादी युवा आंदोलन से जुड़े। जनता पार्टी के दौर में तमिलनाडु में पार्टी अध्यक्ष रहे इरा सेझियन से सीपी राधाकृष्णन का गहरा नाता रहा। 1983 की जनवरी में तत्कालीन जनता पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर ने भारत यात्रा शुरू की थी। तब तमिलनाडु में उनकी यात्रा से जुड़े आयोजनों की व्यवस्था में 28 वर्षीय युवा सीपी ने अहम भूमिका निभाई। तब चंद्रशेखर की उन पर नजर पड़ी।

बाद में रोजगार के लिए होजरी के कारोबार से जुड़े सीपी का नाता शरद यादव से भी रहा। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार के दौरान शरद यादव कपड़ा राज्यमंत्री थे। उन दिनों उन्होंने कोयंबटूर का दौरा किया था, तब शरद यादव के लिए सीपी ने भोज दिया था।

बाद के दिनों में सीपी भाजपा से जुड़ गए और देखते ही देखते भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष बना दिए गए। उनकी अध्यक्षता में ही बीजेपी ने 1998 और 1999 का चुनाव लड़ा और चार सीटों पर जीत हासिल की। पहली बार जहां पार्टी का जयललिता की एआईडीएमके से समझौता था तो दूसरी बार डीएमके के साथ पार्टी चुनाव मैदान में उतरी। यह बात और है कि उन्हें बाद में चुनावी जीत हासिल नहीं हो पाई। 2004, 2014 और 2019 के चुनावों में उन्हें पार्टी ने लगातार कोयंबटूर से उम्मीदवार बनाया, लेकिन हर बार उन्हें हार ही मिली। सिर्फ 2009 में उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया था।

सीपी राधाकृष्णन की अब व्यस्तता बढ़ गई है। अन्यथा दिल्ली में सांसद रहने के दौरान उनका घर सबके लिए खुला रहता था।

सीपी राधाकृष्णन के पिता जी बेहद सहज थे। वे जीवन बीमा निगम के लिए काम करते थे। उनकी पत्नी गृहिणी हैं, जबकि बेटा मानचेस्टर से टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करके कोयंबटूर में पारिवारिक होजरी और स्पिनिंग प्रोडक्शन का कारोबार देखता है। सीपी की एक बेटी भी है। जो अपनी पारिवारिक जिंदगी में व्यस्त है।

कांग्रेसी परिवार में जन्म लेकर समाजवादी धारा की राजनीति के जरिए बीजेपी में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराते हुए देश की आर्थिक राजधानी के राजभवन पहुंचना मामूली बात नहीं है। मौजूदा माहौल में महाराष्ट्र की राजनीति राज्यपाल के बेहद चुनौतीपूर्ण है। अगर थोड़ी भी ऊंचनीच हुई तो राज्यपाल पर ही सबसे भार होगा। देखना है कि सीपी आने वाली चुनौतियों का सामना करते हैं...

बाढ़ के पानी का प्रबंधन कौन करे

क्षमा शर्मा

दो -तीन दिन पहले की बात है। एक स्थान से गुजर रही थी, तो वहां एक बड़ा होर्डिंग लगा देखा। जिस पर लिखा था कि वर्षा जल की एक-एक बूंद बचाना जरूरी है। ऐसे विज्ञापन अक्सर ही नजर आते हैं। अपनी मूल प्रतिज्ञा में यह बात बहुत अच्छी भी लगती है।

दो -तीन दिन पहले की बात है। एक स्थान से गुजर रही थी, तो वहां एक बड़ा होर्डिंग लगा देखा। जिस पर लिखा था कि वर्षा जल की एक-एक बूंद बचाना जरूरी है। ऐसे विज्ञापन अक्सर ही नजर आते हैं। अपनी मूल प्रतिज्ञा में यह बात बहुत अच्छी भी लगती है। वैसे भी अपने यहां कहावत है कि बूंद-बूंद से घट भरे। दशकों से यह घोषणा भी की जाती रही है कि अगला विश्व युद्ध पानी के लिए ही होगा। भारत में जल संचयन की विविध तकनीकें पहले से ही मौजूद हैं। राजस्थान जहां सबसे कम बारिश होती है वहां की जल संचयन की प्रविधियों के बारे में मशहूर पर्यावरणविद् स्वर्गीय अनुपम मिश्र ने 2 अद्भुत पुस्तकें लिखी थीं। 'आज भी खरे हैं तालाब' और 'राजस्थान की रजत बूंदें'। अनेक संस्थाएं भी पानी बचाने की तमाम विधियों पर काम करती हैं।

बुंदेलखंड में पानी बचाने के लिए खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़ जैसे नारों का बोलबाला है। पहाड़ों में भी पानी के संचयन की अनेक तरकीबें मौजूद रही हैं। मगर अफसोस की बात है कि ये सब तकनीकें तथाकथित विकास की भेंट चढ़ चुकी हैं। जिन नदियों को हम देवी मानते हैं, पूजते हैं, उन्हें इस कदर प्रदूषण झेलना पड़ रहा है कि बहुत-सी नदियों का पानी ई-लैबल तक का नहीं रहा है। यानी कि पीने की बात छोड़िए वह जानवरों को नहलाने तक के लिए अनुपयोगी है। इनमें गंगा और यमुना जैसी नदियां भी शामिल हैं। खैर, एक तरफ बूंद-बूंद जल बचाने की बातें हैं तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इन दिनों देश के अधिकांश प्रदेश बाढ़ में डूबे हैं। लोगों के घरों, दुकानों, स्कूलों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों तथा हवाई अड्डों पर पानी भरा है। फसलें नष्ट हो गई हैं। लोग अपने घर-बार छोड़कर भाग रहे हैं।

घर में तबाही देखें कि अपनी जान बचाएं। नदियां, झरने सब उफन रहे हैं। कहीं घर धराशायी हो रहे हैं तो कहीं पुल भरभराकर टूट रहे हैं। मवेशी बहे जा रहे हैं। सड़कें पानी से भरी हैं। लोग जहां हैं, वहीं फंसे हैं। पता नहीं इनमें से कितने बीमार भी होंगे, मगर आने-जाने के रास्ते हों तब तो अस्पताल तक पहुंचें। अस्पताल पहुंच भी जाएं तो क्या पता कि अस्पताल भी पानी में डूबा हो। एक लड़के ने डूबते बछड़े को अपनी जान पर खेलकर बचाया है। इसी तरह एक मुसलमान व्यक्ति ने 6 कांवडियों को अपनी परवाह न करके बाहर निकाला है। बाढ़ का यह कहर इस बार की तो बात नहीं है। हर बार हम ऐसे ही दृश्य देखते हैं। भरे पानी में करंट आने से कइयों की मृत्यु की बातें भी सुनते हैं। लेकिन मौसम बदलता है, तो बाढ़ और नदियों, झरनों के उग्र रूप भी भुला दिए जाते हैं, यह सोचकर कि अगली बार जब कुछ होगा तब देखेंगे और अगली बार पिछली बार से भी भयानक मंजर देखने को मिलते हैं। क्या ऐसा असंभव है कि इतना बड़ा यह देश अपने अतिरिक्त पानी का प्रबंधन न कर सके। बाढ़ के इस पानी के संचयन के लिए ऐसे प्रबंध क्यों नहीं किए जाते कि अतिरिक्त पानी जैसे ही नदियों में आए वह तबाही मचाने के मुकाबले कहीं इकट्ठा किया जा सके।

इस पानी के कारण हमारा घटता भूजल बढ़ सकता है। नदियां सूखने से बच सकती हैं। जो मीठा पानी समुद्र में मिलकर खारा बन जाता है और पीने के लायक नहीं रहता, उसे बचाकर न केवल मनुष्यों बल्कि पशु-पक्षियों यहां तक कि फसलों की प्यास बुझाई जा सकती है। सूखे से निपटा जा सकता है।

– :सौजन्य :–
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV Drive the Future

एक दिन में 1,000 यूनिट रिज़्टा इलेक्ट्रिक स्कूटर वितरित

परिवहन विशेष न्यूज

एथर ने हाल ही में इस महीने की शुरुआत में अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर रिज्टा की डिलीवरी शुरू की थी, जिसके बाद अब ब्रांड ने एक दिन में इस ईवी स्कूटर की 1000 यूनिट डिलीवर करके एक नया मील का पत्थर हासिल कर लिया है। कंपनी ने महाराष्ट्र में केवल 501 स्कूटर डिलीवर किए हैं, जबकि बाकी की डिलीवरी जयपुर, इंदौर और अन्य साउथ इलाकों में की गई है।

अब कंपनी ने देशभर में एथर रिज्टा की डिलीवरी भी शुरू कर दी है। एथर रिज्टा की बात करें तो यह कंपनी का पहला मॉडल है जिसे परिवार को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें दूसरे स्कूटरों के मुकाबले ज्यादा स्पेस है और उपयोगिता के मामले में यह स्कूटर अपने दूसरे मॉडल्स के मुकाबले थोड़ा ज्यादा आरामदायक लगता है।

रिज़्टा दो अलग-अलग वैरिएंट में उपलब्ध है, जिसका नाम S और Z वैरिएंट है। यह तीन बैटरी पैक विकल्पों के साथ भी आता है। एथर रिज़्टा का S वैरिएंट 2.9kWh बैटरी के साथ आता है, जबकि Z वैरिएंट 2.9kWh और 3.7kWh बैटरी विकल्पों के साथ आता है।

सरकार का ध्यान स्वच्छ ऊर्जा साझेदारों पर, 250 अरब डॉलर का होगा इकोसिस्टम

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। सरकार पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। देश में क्लीन मोबिलिटी इकोसिस्टम वित्त वर्ष 2030 तक 250 अरब डॉलर का हो जाएगा, जो 38 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक दर (सीएजीआर) से बढ़ रहा है। प्रैक्सिस ग्लोबल अलायंस की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2030 तक भारत में कुल परिवहन बाजार 1.2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसमें स्वच्छ और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी परिवहन कुल बाजार का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा होगा। प्रैक्सिस ग्लोबल अलायंस के मोबिलिटी, ऊर्जा और परिवहन के प्रबंध पार्टनर आर्यमन टंडन ने कहा, "अपने परिवहन क्षेत्र को विद्युतीकृत करने की दिशा में भारत की यात्रा न केवल एक स्थायी भविष्य की ओर एक छलांग है, बल्कि एक महत्वपूर्ण आर्थिक अवसर भी है।"

भारत में ईवी-टू-चार्जिंग स्टेशन अनुपात 9:1 है। ग्लोबल स्तर पर स्वीकृत मानक अनुपात 4:1 तक पहुंचने के लिए, सरकार ने कई पहल की है, जिनमें एफएएमई 2 में महत्वपूर्ण आवंटन (120 मिलियन डॉलर से अधिक) और ईवी चार्जर्स पर जीएसटी दरों में कमी शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार, "भू-राजनीतिक बदलावों और विनिर्माण लागत में उतार-चढ़ाव के कारण विश्व ईवी बाजार के सामने आने वाली चुनौतियों के बावजूद, भारत इन मुश्किलों का सामना करते हुए भी मजबूती से खड़ा है।"

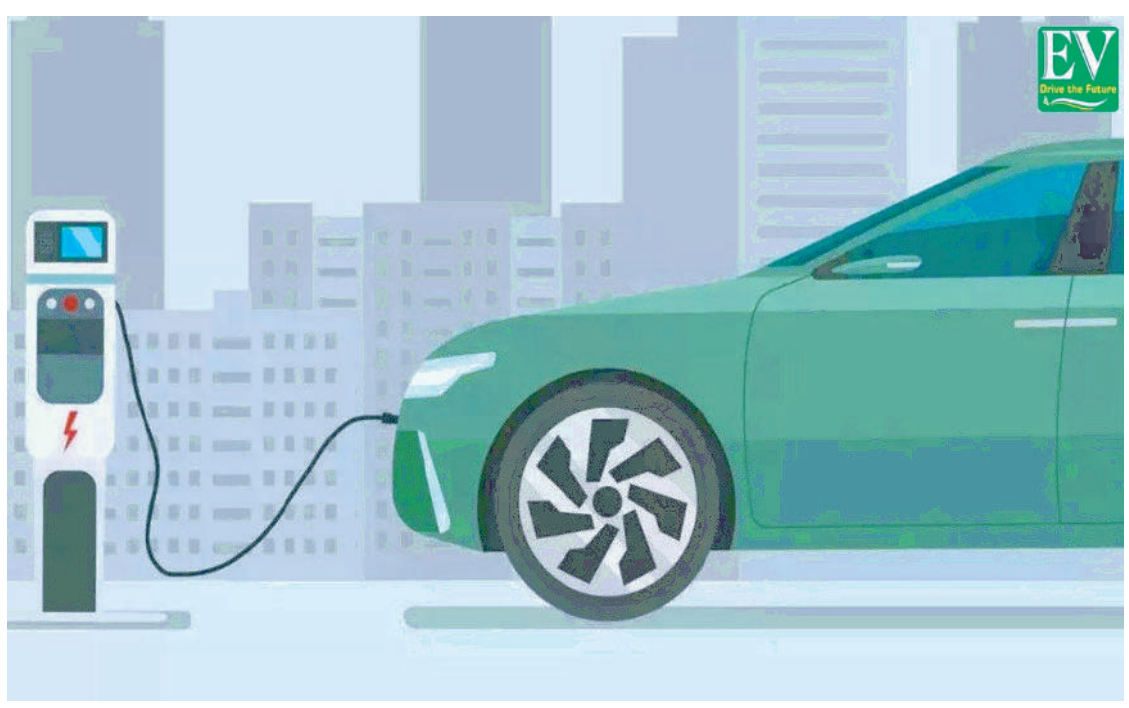

देश की रणनीतिक स्थिति, अनुकूल घरेलू परिस्थितियों और मजबूत नीति ढांचे के साथ, स्वच्छ गतिशीलता (क्लीन मोबिलिटी) को अपनाने के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाता है। अध्ययन के निष्कर्षों के मुताबिक, एकीकृत स्वच्छ गतिशीलता पारिस्थितिकी तंत्र (इंटीग्रेटेड क्लीन मोबिलिटी इकोसिस्टम) विकसित करने पर भारत का जोर न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देता है, बल्कि चार्जिंग बुनियादी ढांचे, बैटरी प्रौद्योगिकी और स्थायी सप्लाई चेन जैसे समर्थन उद्योगों में इनोवेशन को भी बढ़ावा देता है। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और निजी इक्विटी निवेश है, जो ग्रोथ का प्रमुख चालक है।

वित्त वर्ष 2030 तक क्लीन मोबिलिटी प्रोडक्ट के अवसर 94 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। इसका मतलब है कि क्लीन परिवहन के साधनों का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या में काफी वृद्धि होगी और यह 23 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी। भारत में मोबिलिटी सर्विस का अवसर वित्त वर्ष 2024 में 450 अरब डॉलर का है, जिसमें से 80 प्रतिशत से अधिक अवसर परिवहन और लॉजिस्टिक्स सेवाओं में है। रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2024 में सॉफ्टवेयर समाधान अवसर का साइज 0.37 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है, जो 27 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़कर वित्त वर्ष 2030 तक 1.58 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।

हीरो टू-व्हीलर की बिक्री में 85 फीसदी की तेजी; स्प्लेंडर, एचएफ डीलक्स और ग्लैमर का रहा दबदबा

परिवहन विशेष न्यूज

भारतीय मार्केट में हीरो मोटोकॉर्प ने पिछले महीने 4,90,743 यूनिट की बिक्री के साथ टू-व्हीलर सेगमेंट में अपना दबदबा कायम रखा। इसने इस महीने 4,22,740 यूनिट की बिक्री के साथ 16.09% की वृद्धि की है। कंपनी ने अपनी बाइक रेंज के लिए शानदार प्रतिक्रिया मिली है, लेकिन इसके कुछ स्कूटर की बिक्री में गिरावट देखने के लिए मिली है। आइए जानते हैं कि इसकी कौन सी बाइक और स्कूटर की ज्यादा बिक्री हुई है।

जून 2024 में सालाना हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री

हीरो स्प्लेंडर ने जून 2024 में 28.21% की वार्षिक वृद्धि की है। इसकी कुल 3,05,586 यूनिट बिके है। HF Deluxe की बिक्री पिछले महीने मामूली रूप से 0.75% बढ़कर 89,941 यूनिट हो गई, जबकि हीरो ग्लैमर ने जून 2024 में 24,159 यूनिट के साथ 115.88% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। हीरो एक्सट्रीम 125R ने 21,054 यूनिट की बिक्री, जबकि पैशन की बिक्री में सालाना आधार पर 72.45% की गिरावट आई है। हीरो डेस्टिनी 125 ने पिछले महीने की तुलना में 45.24% अधिक बिक्री की है। हीरो प्लेजर की घरेलू बाजारों में मांग के सुधार हुआ है। इसकी सालाना बिक्री में 11.78% बढ़ोतरी हुई है। जूम स्कूटर की बिक्री पिछले महीने की तुलना में 45.04% घटी है।

बिक्री में सबसे नीचे रहा विदा इलेक्ट्रिक स्कूटर

हीरो मोटोकॉर्प की घरेलू बिक्री की सूची में विदा इलेक्ट्रिक स्कूटर सबसे नीचे रहा। जून 2023 में इसकी 2,760 इकाई बिकी थी। हीरो XPulse 200 की बिक्री में भी पिछले महीने 10.68% की वृद्धि हुई, जबकि Xtreme 160/200 की बिक्री में 1.39% की वृद्धि हुई है। करिज्मा की बात करें तो इसकी महज 476 यूनिट बिकी। वहीं, हीरो मैवरिक 400 की बिक्री 459 इकाई रही, जबकि पिछले महीने मैस्ट्रो की 9 इकाई बिकी, जो जून 2023 में बेची गई 2,500 इकाई से 99.64% की गिरावट है।

इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग के कारण रिवोल्ट मोटर्स को सरकारी सब्सिडी से मिलेगा बढ़ावा

परिवहन विशेष न्यूज

भारत में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी रिवोल्ट मोटर्स ने भारत सरकार की ईवी सब्सिडी योजनाओं में भाग लेने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय से आधिकारिक मंजूरी प्राप्त करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह खबर रिवोल्ट मोटर्स द्वारा फेम II कार्यक्रम के तहत प्राप्त पिछली सब्सिडी को सक्रिय रूप से चुकाने के बाद आई है, जो जिम्मेदार कॉर्पोरेट प्रथाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।यह स्वीकृति रिवोल्ट मोटर्स के लिए एक नया अध्याय शुरू करती है। यह उन्हें चल रही इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 के लिए पात्रता प्रदान करती है, जिसमें प्रति इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल 10,000 रुपये की सब्सिडी की पेशकश की जाती है। यह सब्सिडी आगामी फेम III योजना तक भी विस्तारित होने की उम्मीद है। विस्तारित ईएमपीएस 2024, जो 30 सितंबर, 2024 तक वैध है, रिवोल्ट मोटर्स को इस वित्तीय सहायता का लाभ उठाने के लिए एक मूल्यवान अवसर प्रदान करता है।ईवी सब्सिडी भारतीय बाजार में रिवोल्ट मोटरसाइकिलों की प्रतिस्पर्धात्मकता को काफी हद तक बढ़ाएगी। इसका मतलब है कि बिक्री और लाभप्रदता में वृद्धि की संभावना है, जो कंपनी को आगे बढ़ाएगी। इस मंजूरी के साथ, रिवोल्ट मोटर्स निर्माताओं के एक प्रतिष्ठित समूह में शामिल हो गई है जो भारत के अधिक टिकाऊ और ऊर्जा-कुशल भविष्य की ओर संक्रमण को तेज करने के लिए समर्पित है।रिवोल्ट मोटर्स की मूल कंपनी रतनइंडिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड की सह-अध्यक्ष सुश्री अंजलि रतन ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहाः ₹भारी उद्योग मंत्रालय से यह स्वीकृति प्राप्त करके हम बेहद रोमांचित और सम्मानित महसूस कर रहे हैं। यह स्वीकृति हमारी 100% भारतीय निर्मित इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों के साथ मेक इन इंडिया पहल के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता की एक शक्तिशाली पुष्टि है। रिवोल्ट मोटर्स सभी भारतीय नागरिकों को सुलभ और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन समाधान प्रदान करने के अपने मिशन में दृढ़ है।₹रिवोल्ट मोटर्स के लिए ईवी सब्सिडी की मंजूरी भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस वित्तीय सहायता के साथ, कंपनी अपने बाजार हिस्से का विस्तार करने, अनुसंधान और विकास में निवेश करने और देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाने के लिए अच्छी स्थिति में है। जैसा कि रिवोल्ट मोटर्स उच्च गुणवत्ता वाली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों को नया रूप देने और वितरित करने के लिए जारी है, भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग टिकाऊ गतिशीलता की ओर एक परिवर्तनकारी बदलाव देखने के लिए तैयार है।

अमरीकी नौसेना के लिए रडार पुर्ज़े बनायेगी मित्सुबिशि इलेक्ट्रिक

परिवहन विशेष न्यूज

जापान की मित्सुबिशि इलेक्ट्रिक कंपनी ने बताया है कि उसने अमरीकी नौसेना के जहाज़ों की रडार प्रणाली के लिए कल-पुर्ज़ों की आपूर्ति हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

मित्सुबिशि इलेक्ट्रिक ने घोषणा की हैं कि उसने अमरीकी वायु रक्षा उपकरण कंपनी आरटीएक्स के साथ अनुबंध किया है।

वह 2028 के आसपास पुर्ज़ों की आपूर्ति शुरू कर देगी। यह पहली बार होगा जब कंपनी, अमरीकी सेना को रक्षा उपकरण की आपूर्ति करेगी।

मित्सुबिशि की योजना तोक्यो के निकट कामाकुरा स्थित एक कारखाने में इन पुर्ज़ों का निर्माण करने की है।

कंपनी अपने रक्षा कारोबार को आगे बढ़ा रही है। पिछले साल उसने फ़िलीपींस को हवाई निगरानी रडार प्रणाली का निर्यात किया था। जापानी रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के विदेशों को हस्तांतरण के तीन सिद्धांतों पर आधारित, निर्मित रक्षा उत्पादों की यह पहली डिलीवरी थी।

मित्सुबिशि कंपनी, जापान, ब्रिटेन और इटली द्वारा संयुक्त रूप से विकसित अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए रडार और इलेक्ट्रॉनिक पुर्ज़ों पर भी काम कर रही है।

रेंज रोवर स्पोर्ट ईवी टेस्टिंग के दौरान पहली बार हुई स्पॉट, ICE वर्जन से अलग होगा डिजाइन

परिवहन विशेष न्यूज

रेंज रोवर स्पोर्ट ईवी को पहली बार टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। इलेक्ट्रिक वेरिएंट में ICE वर्जन की तुलना में कई बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। जिसमें डिजाइन भी शामिल है। इसके सभी मॉडल 800V चार्जिंग हार्डवेयर से लैस हो सकते हैं। साथ ही यह फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ भी आ सकती है। आइए जानते हैं कि यह किन फीचर्स के साथ आने वाली है।

रेंज रोवर जल्द ही अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लाने की तैयारी कर रहा है। जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी रेंज रोवर स्पोर्ट ईवी को पहली बार टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। जिसमें रेंज रोवर स्पोर्ट ICE की तुलना में डिजाइन में मामूली बदलाव देखने के लिए मिले है। आइए जानते हैं कि स्पॉट की गई रेंज रोवर स्पोर्ट ईवी में क्या नए बदलाव किए गए हैं और यह भारतीय मार्केट में कब आ सकती है।

देखने के लिए मिले नए बदलाव

पुहली बार टेस्टिंग के दौरान स्पॉट की गई रेंज रोवर स्पोर्ट ईवी में DRLs और स्पोर्टी बंपर के साथ वही स्लिम LED हेडलैंप देखे गए हैं। ईवी में ग्रिल थोड़ी अलग दिखाई दे रही है। कंपनी इसे ICE वर्जन से अलग करने के लिए अपग्रेडेड ग्रिल दे सकती है। इसके साथ ही इससे एग्जॉस्ट आउटलेट को हटा दिया गया है। JLR ने अपने आने वाले EV के परफॉर्मेंस की जानकारी जारी नहीं की है। उम्मीद लगाई जा रही है कि इसका परफॉर्मेंस V8 के बराबर होगा।

कैसा होगा बैटरी पैक

JLR ने अभी तक बैटरी के स्पेसिफिकेशन की जानकारी को सामने नहीं आने दिया है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसके सभी मॉडल में 800V चार्जिंग हार्डवेयर देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ ही तेजी से टॉप-अप के लिए 270kW तक की चार्जिंग स्पीड होगी।

कितनी होगी कीमत और कब होगी लॉन्च

रेंज रोवर स्पोर्ट ईवी को पहली टेस्टिंग के दौरान स्पॉट होने के बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि यह इस साल के अंत में पेश हो सकती है। यह ICE वेरिएंट की तुलना में ज्यादा महंगी हो सकती है, जिसकी वर्तमान में एक्स-शोरूम कीमत 1.40 करोड़ रुपये है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है नए अवसर

विजय गर्ग

मेरे कई कार्यकारी छात्रों के लिए, एआई के क्षेत्र में प्रगति आश्चर्यजनक है और ऐसा प्रतीत होता है कि उनके लिए यह तर्क देना कठिन हो गया है कि इस उपकरण को अपनाते समय उन्हें सावधान क्यों रहना चाहिए। उनका ध्यान पूरी तरह से उन वित्तीय लाभों पर है जो एआई अपने साथ लाता है, और उनकी अपनी मानवता के महत्व - और दीर्घकालिक रूप से, शायद अस्तित्व भी - को नजरअंदाज कर देता है।

प्रशिक्षण, शिक्षा और एआई-संचालित उपकरणों के साथ मानवीय क्षमताओं को बढ़ाकर, व्यवसाय नौकरियों की रक्षा करते हुए और विकास को बढ़ावा देते हुए एआई की पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। मानव विकास में दीर्घकालिक निवेश के साथ स्वचालन के नकारात्मक परिणामों का मुकाबला करें। मानव विकास में दीर्घकालिक निवेश के साथ स्वचालन के नकारात्मक परिणामों का मुकाबला करें। श्रम पर स्वचालन का ख़तरा कोई नई बात नहीं है। मनुष्य के पास नई तकनीकों का एक लंबा इतिहास है जो कार्यों को स्वचालित करके हमारे वर्कफ़्लो को बाधित करती है, 1439 में प्रिंटिंग प्रेस से लेकर 1993 में इंटरनेट तक सार्वजनिक पहुंच तक। आज, हमारे पास एक बुद्धिमान तकनीक उपलब्ध है जो श्रम की लागत और लागत दोनों को कम कर सकती है। तर्कहीन (मानवीय) कार्य व्यवहार के खतरे जो सुव्यवस्थित परिचालन प्रक्रियाओं से भटकते हैं। इस बार, स्वचालन का खतरा काफी अलग है क्योंकि एआई की स्व-सीखने की क्षमताएं इसे नकल करने की अनुमति देती हैं और कभी-कभी मनुष्यों की संज्ञानात्मक क्षमताओं पर भी हावी हो जाती हैं'। मेरे कई कार्यकारी छात्रों के लिए, एआई के क्षेत्र में प्रगति आश्चर्यजनक है और ऐसा प्रतीत होता है कि उनके लिए यह तर्क देना कठिन हो गया है कि इस उपकरण को अपनाते समय उन्हें सावधान क्यों रहना चाहिए। उनका ध्यान पूरी तरह से उन वित्तीय लाभों पर है जो एआई अपने साथ लाता है, और उनकी अपनी मानवता के महत्व - और दीर्घकालिक रूप से, शायद अस्तित्व भी - को नजरअंदाज कर देता है। वे अक्सर टिप्पणी करते हैं कि, व्यवसायों के लिए मूल्य बनाने और किसी भी अन्य कर्मचारी की तुलना में आर्थिक विकास में अधिक योगदान देने की एआई की क्षमता को देखते हुए, व्यवसाय के नेताओं के रूप में, उनके पास अकेले दिमाग से स्वचालन रणनीतियों को आगे बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अल्पकालिक परिप्रेक्ष्य से, यह तर्क उचित प्रतीत होता है। दरअसल, स्वचालन को प्राथमिकता के रूप में देखने वाली कंपनियां कुछ प्रदर्शन लाभ दर्ज करेंगी। लेकिन इस कहानी का सार यह है कि संगठन की व्यावसायिक वृद्धि में स्वचालन का योगदान अंततः धीमा हो जाएगा और कभी-कभी उनके विरुद्ध भी काम करेगा। स्वचालन केवल एक अल्पकालिक समाधान है जो

दीर्घावधि में आपके संगठन को ठप कर देगा... स्वचालन रणनीतियों की वास्तविकता यह है कि लोगों की नौकरियाँ छिन्न-भिन्न हो जाती हैं... नौकरी के विखंडन के कारण, कर्मचारी आसानी से कम वेतन वाली नौकरियों में आ जाते हैं। कुछ हद तक, यह विकास नौकरी ध्रुवीकरण की अच्छी तरह से खोजी गई घटना से उत्पन्न होता है। एआई को विकसित करने और तैनात करने में अंतर्निहित सीमाओं के कारण, कम वेतन वाले मैन्युअल काम को स्वचालित करना आम तौर पर बहुत महंगा और कठिन होता है (उदाहरण के लिए, सफाई रोबोट को तैनात करने की तुलना में क्लीनर को किराए पर लेना अक्सर सस्ता और अधिक कुशल होता है)। दूसरी ओर, उच्च-भुगतान वाले रचनात्मक और रणनीतिक कार्यों को स्वचालित करना बहुत महंगा और कठिन है। इससे नौकरियों का मध्य खंड - नियमित प्रशासनिक, नौकरशाही कार्यालय कार्य - स्वचालन के मुख्य लक्ष्य के रूप में रह जाता है। और जब ऐसे श्रमिकों को विस्थापित किया जाता है, तो वे उच्च वेतन वाले काम करने के लिए तुरंत कौशल विकसित नहीं कर सकते हैं। परिणामस्वरूप, वे कम वेतन और निम्न दर्जे के काम में लग जाते हैं, ऐसे पद जो असमानता को और बढ़ाते हैं। 'इसलिए, एक एआई-प्रेमी नेता के रूप में, आपको पूरी तरह से जागरूक होने की आवश्यकता है कि केवल स्वचालन पर ध्यान केंद्रित करने वाले एआई प्रयास तेजी से नैतिक और निष्पक्षता जोखिम लाएंगे। आपके स्वचालन प्रयास नौकरी ध्रुवीकरण को बढ़ा सकते हैं और सामाजिक आर्थिक असमानता को बढ़ा सकते हैं, जो अशांति, अस्थिरता और अन्य अस्थिरता, यहां तक कि हिंसा को भी जन्म दे सकता है। बदले में, असमानता के प्रति ये प्रतिक्रियाएँ आपके संगठन को खतरे में डाल देंगी, जो कम मानवीय हो गया है और इसलिए अस्थिरता को समायोजित करने में कम सक्षम है। जिस तरह से आप कर सकते हैं बहुत अधिक स्वचालन के नकारात्मक परिणामों का मुकाबला आपके संगठन में मानवीय कार्यों के निर्माण में दीर्घकालिक निवेश के माध्यम से होता है। वृद्धि के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए गंभीर निवेश की आवश्यकता है, क्योंकि नई नौकरियों में कर्मचारियों को सीखने और खुद का एक बेहतर संस्करण बनने के लिए विकसित करने के लिए समृद्ध कार्य सामग्री और अतिरिक्त संज्ञानात्मक जिम्मेदारियों की आवश्यकता होगी। इन नई नौकरियों में, जहां एआई और इंसान एक साथ काम करेंगे, आपके कर्मचारियों को एक सहकर्मी के रूप में स्मार्ट मशीन रखने की आदत डालने में मदद करने के लिए आवश्यक कौशल हासिल करने की आवश्यकता होगी। आप जो सबसे अधिक चाहते हैं वह यह है कि आपके कर्मचारी एक प्रमुख क्षमता में बेहतर हों जो मनुष्य जीवन में जल्दी विकसित होता है और जिससे कंपनियों को सबसे अधिक लाभ होता है: रचनात्मकता। रचनात्मक प्रक्रिया में, मानव एक समस्या की पहचान करता है, जो एआई द्वारा संचालित पीढ़ी प्रक्रिया में इनपुट के रूप में काम करेगा, और उत्पन्न आउटपुट को फिर मानव द्वारा व्याख्या, सही और नियोजित किया जाएगा। इस प्रकार रचनात्मकता प्रक्रिया को शुरू करने और समाप्त करने के लिए एक इंसान की आवश्यकता होती है, जबकि एआई पीढ़ी प्रक्रिया को संचालित करता है जिसमें सभी सूचनाओं को एक साथ लाने का कठिन श्रम शामिल होता है। एआई का सर्वोत्तम लाभ उठाने के लिए, आपको अपनी प्राथमिकता के रूप में स्वचालन को खरीदने से बचना होगा और इसके बजाय वास्तविक वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उस परिणाम को प्राप्त करने के लिए, आपको निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे। यह एक विशिष्ट प्रतिक्रिया है जो मैंने कंपनियों की एआई अपनाने वाली परियोजनाओं पर चर्चा करते समय सुनी है। जैसा कि कई परिवर्तन सलाहकार आपको बताएंगे, जब संगठन अपनी एआई अपनाने की परियोजना शुरू करते हैं, तो वे आमतौर पर अपने बजट का 90 प्रतिशत तक प्रौद्योगिकी पर ही खर्च करते हैं। इसका परिणाम यह है कि एआई को कार्यबल के साथ मिलकर काम करने के लिए बहुत कम पैसा बचा है। यह परिणाम खेदजनक और प्रतिकूल दोनों है। यह आपके एआई अपनाने के प्रोजेक्ट की सफलता की संभावना को कमजोर कर देगा। यदि, अब तक, आपने एआई पर अच्छी व्यावसायिक जानकारी प्राप्त कर ली है, तो आप जानते हैं कि अपने कर्मचारियों के लिए बेहतर, अधिक मानव-केंद्रित नौकरियां बनाने में अधिक - अधिक समय, अधिक पैसा - निवेश करना आपका दायित्व है, क्योंकि यह सही बात है। करना है और क्योंकि इसे न करने की दीर्घकालिक लागतें महत्वपूर्ण हैं। सबसे सफल कंपनियां वे हैं जो एआई अपनाने की परियोजना शुरू होने पर अपने लोगों में भारी निवेश करती हैं।

सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शैक्षिक स्तंभकार

संपादक की कलम से

कोचिंग हादसे के सबक

क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, तिहाड़ जेल से ही, अपनी सरकार की जवाबदेही स्वीकार करेंगे? क्या वह यह भी स्वीकार करेंगे कि उनकी आम आदमी पार्टी (आप) दिल्ली में सरकार और नगर निगम चलाने लायक नहीं है? क्या केजरीवाल अब दिल्ली वालों का आह्वान करेंगे कि चुनाव में 'आप' को बहुमत न दिया जाए? राजधानी दिल्ली में तीन युवाओं की जो दर्दनाक, त्रासद मौतें हुई हैं या ऐसे ही हादसे हो रहे हैं, क्या उनके पीछे भी प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा की साजिश है? दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल के नेतृत्व में निर्वाचित सरकार है। जेल में बंद होने के बावजूद वह मुख्यमंत्री हैं। सर्वोच्च अदालत के नैतिक संकेत के बावजूद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने को तैयार नहीं हैं। सरकार में उपमुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया भी जेल में हैं। जो बचे-खुचे मंत्री हैं, वे सिर्फ बयानवीर हैं अथवा उपराज्यपाल पर दोषारोपण करने वाले नेता हैं। वे 'बेचारगी के प्रतिनिधि' हैं, जो बयान देने या जांच की लीपापोती के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो फिर 'मंत्री' क्यों बने बैठे हैं? इस्तीफा देकर, सडक़ पर उतर कर, लोकतंत्र की लड़ाई क्यों नहीं लड़ते? दिल्ली में सरकार 'आप' की है और नगर निगम पर भी वह काबिज है। मेयर शैली ओबरॉय 'आप' की ही नेता हैं। इन जवाबदेहियों का जिक्र इसलिए करना पड़ रहा है या ये सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में विधानसभा स्तर पर जो सरकार है, वह गायब है, लिहाजा स्थानीय दिल्ली 'अनाथ' महसूस कर रही है। तीन युवा छात्रों की पानी के तेज बहाव में, एक इमारत के बेसमेंट में फंस कर, मौत हो गई। यह आपदा या हादसा नहीं, हत्याकांड है। उस इमारत में आईएएस की कोचिंग देने वाला प्रख्यात केंद्र चलता है, जिसके बड़े-बड़े विज्ञापन अखबारों में छपते हैं और युवा छात्रों को आकर्षित करते रहे हैं। यह केंद्र कोचिंग देने की फीस लाखों में लेता है, लेकिन सुविधा और सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। उस इमारत के बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाई गई है, जो कानूनन अवैध है। जो छात्र बच गए हैं, उनकी नियति ही ऐसी थी, अलबत्ता पानी का बहाव किसी बाढ़ से कम नहीं था। वहां इतना तेज पानी कैसे घुसा? इसी सवाल के गर्भ में तमाम भ्रष्टाचार और कदाचार निहित हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के पास मुखर्जी नगर की वह घटना आज भी याद आती है, जब आग से बचने के लिए युवा छात्रों ने खिड़कियों से ही छलांग लगा दी थी अथवा किसी रस्सी के सहारे, जलते हुए कमरे से, बाहर कूद पाए थे। कुछ मौतें भी हुई थीं। वहां भी आईएएस, आईपीएस बनने का सपना पाले युवा छात्र पढ़ते हैं। वहां भी बंदप्रायः कोचिंग सेंटर में आग लगी थी। अभी 4-5 दिन पहले दिल्ली के पटेल नगर में एक युवा करंट की चपेट में आकर मारा गया। वह भी आईएएस की तैयारी कर रहा था। ये आपराधिक नाकामियों की भयावह कथाएं हैं, लापरवाही को नंगा करती हैं, आखिर दिल्ली में ये हत्याकांड क्यों हो रहे हैं? व्यवस्था और निगरानी की बुनियादी और प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी है? जाहिर है कि केजरीवाल की सरकार और 'आप' के नगर निगम की जिम्मेदारी है। ड्रेनेज सिस्टम और नालों की सफाई कौन देखेगा? दिल्ली में तो इतनी बारिश भी नहीं हुई है कि व्यवस्थाएं ही डूब जाएं। आईएएस कोचिंग सरीखे 550 से अधिक केंद्र दिल्ली में चल रहे हैं, जिनमें से 60-65 ही पूरी तरह 'वैध' हैं। अधिकतर इमारतों में अग्नि-सुरक्षा के न तो बंदोबस्त हैं और न ही प्रमाणपत्र हैं। उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है, क्योंकि ऊपर तक 'मुंह में दही' जमाई हुई है। अब ये नजराने किस स्तर तक दिए जाते रहे हैं, यह जांच का विषय है, जिसका कोई ठोस निष्कर्ष कभी सामने नहीं आएगा। इस हत्याकांड के बाद युवाओं में आक्रोश है, वे विद्रोह पर उतारू हैं, हत्या का केस दर्ज किए जाने के आग्रह कर रहे हैं।

अब प्रशासन ने इमारतों के ऑडिट करने का फैसला लिया है। उससे भी क्या होगा, क्योंकि प्रशासन ने ही आंखें मूंदी हुई हैं, कान भी बंद कर रखे हैं, संज्ञान पर सन्नाटा छाया है। शोकाकुल माता-पिता इक_ा होकर प्रधानमंत्री आवास पर जाएं और उन्हें मुलाकात के लिए बाध्य करें, ताकि राजधानी में कमोबेश युवा छात्रों की कोचिंग वाले केंद्रों की व्यवस्था नए सिरे से दुरुस्त कराई जा सके। दिल्ली के उप राज्यपाल छात्रों से मिले हैं और उनकी समस्याओं का संज्ञान लिया है।

राय

आत्मनिर्भरता के टूल

सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने हिमाचल के बंधे हाथों में नई ऊर्जा और जल स्रोतों में आर्थिक करंट पैदा किया है। सर्वोच्च अदालत ने प्राकृतिक संपदा के कानूनी अधिकारों में नए मार्गदर्शन देते हुए राज्यों को खदानों का संवैधानिक प्रश्रय दिया है। अब खनिजों पर सारे कानूनी व आर्थिक अधिकार राज्यों को प्राप्त हो गए, तो जाहिर तौर पर इससे केंद्र की लंबी परछाइयां खत्म होंगी। जिन कुंडिलयों के तहत हिमाचल की बांध और बिजली परियोजनाओं पर केंद्र की हिदायतें जुल्म ढहाती थीं, वे अब बीते समय की बात होगी, तो फिर तमाम केंद्रीय एजेंसियों के तहत हो रहे विद्युत उत्पादन की मुफ्त रॉयल्टी से कहीं आगे वाटर सैस पर लगे अडंगों तक जाएगी और तब सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देश हिमाचल के खजाने का संबल बनेंगे। इस परिप्रेक्ष्य में पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के कार्यकाल से शुरू हुई कोशिशें सुक्खू साम्राज्य तक आते-आते अब फलीभूत हो सकती हैं। हिमाचल का संघर्ष अपनी ही प्रकृति और प्रवृत्ति से है। मौसम से है और बहते हुए उस पानी से है, जिसने इस क्षमता को हमारी बेबसी बनाए रखा। हम टीहरी बांध या नर्मदा बांध परियोजनाओं से भी गए गुजरे इसलिए हो गए, क्योंकि पौंग व गोबिंद सागर जलाशयों के राष्ट्रीय फायदों के मुजरिम समझे गए। आश्चर्य यह कि ये बांध परियोजनाएं हमें डुबो कर बिजली और पानी से पड़ोसी राज्यों को सशक्त करती रहीं। शानन जैसी विद्युत परियोजना की लीज समाप्ति के बाद भी हम इसके हकदार नहीं हुए, क्योंकि जल संसाधन पर केंद्रीय सोच की कुंडली रही। अब एक नया कानूनी दृष्टिकोण सामने आ रहा है, तो वर्षों पहले से जनरेशन टैक्स लगाने की वजह और हिम्मत हम कर सकते हैं। कुछ इसी तरह के आर्थिक अधिकार पहाड़ी प्रदेशों को पर्यावरण सुरक्षा के नाम पर मिलने चाहिएं। आखिर सत्तर फीसदी जमीन को जंगलों के सुपुर्द कर देने से हिमाचल को मिला क्या।

गर्मियों में आग, तूफान में पेड़ों के गिरने से नुकसान और वनापत्तियों के लिए कठोर लगाम के सिवा इस तपस्या का हासिल क्या हुआ। आश्चर्य यह कि जंगल की आग या पेड़ों के गिरने से स्वाह होती चल-अचल संपत्तियों के लिए भी वन विभाग खुद की जिम्मेदारी नहीं मानता। एक अलग संदर्भ में ही सही, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय का सुझाव व्यावहारिक व प्रदेश हित में आर्थिक उपचार सरीखा है। माननीय अदालत प्रदेश की पर्यावरणीय स्वच्छता के लिए पर्यटक शुल्क का सुझाव दे रही है ताकि हर साल इस उद्योग के मार्फत पैदा हो रही चुनौती से निपटने का वित्तीय संबल मिले। पूरे हिमाचल में मनाली की तर्ज पर ग्रीन टैक्स लगाया जाए तो पर्यटन उद्योग की वांछित सुविधाओं, अधोसंरचना निर्माण के अलावा स्वच्छता इंतजाम के लिए आवश्यक धन उपलब्ध होगा। बहरहाल केंद्र सरकार के सामने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एक तरह से आर्थिक सुधारों व केंद्र-राज्य संबंधों के लिए एक नई इबारत है। इससे कमोबेश हर राज्य को आर्थिक विकास का कोई न कोई रास्ता मिलेगा, जबकि पर्वतीय परिप्रेक्ष्य में पहली बार जल के मार्फत तकदीर का फैसला हुआ है। कुछ इसी तरह राज्य के विभिन्न अधिकारों खासतौर पर पर्यावरणीय व वन भूमि के घनत्व के अनुरूप आर्थिक संसाधन या केंद्रीय बजट आबंटन हो। मसलन हरियाणा और पंजाब में पांच प्रतिशत से भी कम भूमि पर जंगल माने गए हैं, जबकि हिमाचल और उत्तराखंड की करीब सत्तर फीसदी भूमि वनों के तहत है। ऐसे में वन भूमि की प्रतिशतता को देखते हुए इसकी आर्थिक भरपाई होनी चाहिए।

नीट की विश्वसनीयता संदेह से परे स्थापित की जाऐ

विजय गर्ग

मेडिकल की पढ़ाई के लिए योग्य छात्रों का चयन करने की इस वार्षिक कवायद पर संदेह के बड़े बादल मंडरा रहे हैं। नीट में उन्हें जो रैंक मिलती है, उसका उनके भविष्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले, मांग और आपूर्ति का प्रश्न। बताया गया है कि 'लगभग 23 लाख 33 हजार अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। ये छात्र 1.08 लाख सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, जिनमें से 56000 सीटें सरकारी कॉलेजों में थीं और बाकी निजी संस्थानों में थीं। इस वर्ग से बाहर रह गए लोग आवश्यक रूप से बिना योग्यता वाले छात्र नहीं हैं। बात सिर्फ इतनी है कि सीटों की चाह में उन्हें बाहर कर दिया गया है। क्या यह अनुचित नहीं है?

कम सीटें होने से मुकाबला कड़ा हो गया है. युवा छात्रों पर दबाव घबराहट पैदा करने वाला है। कई युवा अवसाद में चले जाते हैं या आत्महत्या जैसा कदम भी उठा लेते हैं।

इसलिए, सरकारों को इच्छुक छात्रों के लिए अधिक मेडिकल कॉलेज और अधिक सीटें उपलब्ध करानी होंगी। यह सरकारी या निजी क्षेत्र में हो सकता है। इसे संभव बनाने के तरीके खोजने होंगे।

यहीं पर कोचिंग संस्थान आते हैं, जो छात्रों और उनके अभिभावकों की हताशा का फायदा उठाते हैं। अक्सर परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर इन कोचिंग संस्थानों पर उंगली उठती रहती है. जनता की धारणा यह है कि हर पाई में उनकी उंगली है, चाहे वह एनईईटी या जेईई या यहां तक कि यूपीएससी हो।

नीट या जेईई जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा पर ही पुनर्विचार किया जाना चाहिए। जब एक राष्ट्रव्यापी परीक्षा आयोजित की जाती है, तो कहीं न कहीं सिस्टम में हेराफेरी करना काफी संभव है। सर्वत्र भ्रष्टाचार के जाल को देखते हुए इसे ऊपर से नीचे तक कदाचार मुक्त बनाना असंभव है।

राज्य-व्यापी प्रवेश परीक्षा अधिक उचित है

सिस्टम को बेहतर ढंग से काम करने के लिए देश के प्रत्येक राज्य द्वारा अपनी प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की पिछली प्रणाली को पुनर्जीवित किया जा सकता है। एक और गारंटी के रूप में, प्रवेश परीक्षा और बोर्ड परीक्षा के लिए समान वेटेज (50% प्रत्येक) छात्रों की सापेक्ष रैंकिंग निर्धारित कर सकता है। इस व्यवस्था में कदाचार की संभावना कम होती है।

बोर्ड परीक्षा और प्रवेश परीक्षा को समान श्रेय देने से छात्रों के बीच समानता स्थापित होगी क्योंकि आज सीबीएसई के छात्रों को एनईईटी और जेईई दोनों में दूसरों पर बढ़त हासिल है।

दूसरे बोर्ड के छात्रों की इसी कमजोरी को कोचिंग संस्थान भुनाते हैं।

कुछ राज्य सरकारें पहले ही अपने छात्रों के केंद्रीकृत परीक्षण के प्रति अपनी अस्वीकृति व्यक्त कर चुकी हैं। उन्हें लगता है कि इस प्रणाली में उनके छात्रों को नुकसान हो रहा है और राज्य बोर्डों के छात्रों के साथ केंद्रीय बोर्ड के छात्रों के बराबर व्यवहार करना बेहद अनुचित है।

'शिक्षा' समवर्ती सूची में होने के कारण, राज्य सरकारों को इस मामले में हिस्सेदारी और अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए।

एनटीए संचालन की गहन समीक्षा करने और उनके सिस्टम की दक्षता में सुधार और मजबूती के लिए प्रोटोकॉल का सुझाव देने के लिए सरकार द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। आइए बेहतरी की आशा करें।

मामले की जड़ प्रवेश परीक्षाओं की वैधता है। यह निंदनीय है कि कुछ बुरे तत्व प्रश्नपत्र लीक करते हैं और पैसा कमाते हैं, इस प्रकार सिस्टम पर अपनी नाक ठोंकते हैं। लाखों छात्रों से जुड़े एक विशाल कार्य को भीतर और बाहर से कुछ बेईमान तत्वों द्वारा फिरौती के लिए आयोजित किया जाता है। ये रुकना चाहिए. दोषियों को न्याय के कठघरे में लाया जाना चाहिए और अनुकरणीय दंड दिया जाना चाहिए। हमें सिस्टम को साफ-सुथरा बनाना होगा और इसे बिल्कुल दोषरहित, निष्पक्ष और कुशल बनाना होगा।

सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शैक्षिक

विजय गर्ग

वेडिंग प्लानर - वेडिंग प्लानर कैसे बनें

वेडिंग प्लानर एक पेशेवर है जो शादी करने वाले जोड़े के जीवन को आसान बनाता है। वह यह सुनिश्चित करके ऐसा करता है कि शादी के प्रत्येक तत्व चाहे वह सजावट, कपड़े, फोटोग्राफी, भोजन या फूलों की व्यवस्था हो। वह इनका समन्वय और संचालन इस तरह से करता है कि शादी का दिन वास्तव में सभी उपस्थित लोगों के लिए यादगार बन जाता है। इससे पहले, जोड़े के दोस्त और परिवार ही थे जिन्होंने जोड़े की शादी के आयोजन की जिम्मेदारी ली थी। हालाँकि, आजकल, जैसा कि हर कोई एक आदर्श, इस दुनिया से हटकर सपनों की शादी चाहता है, लोग इस काम के लिए किसी पेशेवर की सेवाएं लेना पसंद करते हैं। वेडिंग प्लानर अल्ट्रा-ग्लैमर पेशेवर हैं, जिनका एकमात्र काम डेकोरेटर, कैटरर्स और अन्य सभी विक्रेताओं को अपना काम ठीक से करने का आदेश देना है। वे शादी की तैयारियों के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं। वे शादी से पहले, शादी के दिन और उसके बाद भी कई कर्तव्य निभाते हैं। शुरुआत करने के लिए, जब एक वेडिंग प्लानर को काम पर रखा जाता है, तो वह जोड़े से मिलता है और यह आकलन करने की कोशिश करता है कि वे किस तरह की शादी की उम्मीद कर रहे हैं। वेडिंग प्लानर उनके साथ बजट, आमंत्रित लोगों की संख्या, उनके मन में शादी की कोई विशिष्ट थीम, कुछ अनिवार्य शादी परंपराओं आदि के बारे में चर्चा करते हैं। वेडिंग प्लानर पात्रता शैक्षणिक योग्यता वेडिंग प्लानर बनने के लिए कोई विशेष डिग्री नहीं है, लेकिन अगर आप कोई बड़ा बिजनेस चाहते हैं तो कुछ ऐसे कोर्स हैं जिनके लिए योग्यता 12वीं या इसके समकक्ष होनी चाहिए। वेडिंग प्लानर के लिए आवश्यक कौशल वेडिंग प्लानर्स के पास उत्कृष्ट संगठनात्मक कौशल होना चाहिए; एक समय में एक से अधिक कार्य करने की क्षमता; अच्छा संचार और लोगों का कौशल। उनके पास अच्छा ग्राहक सेवा कौशल होना चाहिए; समस्या-समाधान कौशल और अप्रत्याशित से निपटने की क्षमता और विस्तार पर उत्कृष्ट ध्यान। उनमें दबाव में काम करने और समय सीमा को पूरा करने की क्षमता होती है; बिक्री और बातचीत कौशल; बजट प्रबंधित करने की क्षमता. उनमें एक टीम के हिस्से के रूप में और आपकी पहल पर भी काम करने की क्षमता होती है; उत्साह, प्रेरणा और एक मिलनसार, मिलनसार व्यक्तित्व और एक आत्मविश्वासी और दृढ़ स्वभाव। वेडिंग प्लानर्स के पास फैशन की अच्छी समझ होनी चाहिए; रंग, संगीत, फूलों और धर्मों के अच्छे ज्ञान के बारे में जानें। उन्हें आतिथ्य सत्कार, कार्यक्रम योजना, सजावट और शादी के रुझानों और परंपराओं में भी विशेषज्ञ होना चाहिए। वेडिंग प्लानर कैसे बनें? एक व्यक्ति को वेडिंग प्लानर बनने के लिए दिए गए चरणों का पालन करना होगा: स्टेप 1 छात्रों को इवेंट प्लानिंग पेशे का बारीकी से अध्ययन करना चाहिए और विभिन्न पुस्तकों, पत्रिकाओं को ब्राउज़ करना चाहिए और उद्योग में नए रुझानों से खुद को अपडेट रखना चाहिए। कई शैक्षणिक संस्थान विवाह नियोजन प्रमाणपत्र/डिग्री पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं जो संभावित ग्राहकों को प्रदर्शित कर सकते हैं कि आप इस क्षेत्र में योग्य हैं। वे इवेंट प्लानिंग में स्नातक या एसोसिएट डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। डिग्री/प्रमाणपत्र/डिप्लोमा पाठ्यक्रम: विवाह योजना में प्रमाणपत्र वेडिंग और इवेंट फोटोग्राफी में डिप्लोमा वेडिंग प्लानिंग में डिप्लोमा बी ० ए। (ऑनर्स) (इवेंट मैनेजमेंट) चरण दो जो छात्र अधिक पेशेवर बनना चाहते हैं या बड़े विवाह व्यवसाय प्रबंधन करना चाहते हैं, उनके लिए स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद मास्टर डिग्री है। यहां, आप शादी की व्यवस्था में आधुनिक तकनीक के उपयोग के साथ प्रबंधन कौशल सीखते हैं। मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम: एम.बी.ए. (इवेंट मैनेजमेंट) इवेंट मैनेजमेंट के मास्टर संस्थान कावेडिंग प्लानर के लिए पाठ्यक्रम की पेशकश नेशनल एकेडमी ऑफ इवेंट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, अहमदाबाद क्राफ्ट फिल्म स्कूल, दिल्ली दिल्ली स्कूल ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, दिल्ली द वेडिंग एकेडमी, मुंबई वेडिंग प्लानर नौकरी विवरण उनकी कुछ कार्य गतिविधियाँ नीचे उल्लिखित हैं: रेखाचित्र और नमूना डिज़ाइन तैयार करना। डिज़ाइन में सहायता के लिए विशेषज्ञ कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर का उपयोग करना। व्यापार मेलों में भाग लेना और डिज़ाइन प्रदर्शित करना। मूल्यांकन के लिए ग्राहकों को डिज़ाइन और नमूने प्रस्तुत करना। अनुबंधों पर बातचीत करने के लिए. फैशन और कपड़ा डिज़ाइन रुझानों के साथ अपडेट रहने के लिए। वेडिंग प्लानर कैरियर संभावनाएं कोर्स पास करने के बाद छात्र किसी बड़े इवेंट संगठन या संबंधित क्षेत्रों में प्रबंधन की भूमिका निभा सकते हैं, या आप वेडिंग प्लानर या डिजाइनर बनने के उनके सपने को पूरा करने में सक्षम होंगे। यदि आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने से पहले कुछ अनुभव प्राप्त करने के लिए किसी के अधीन काम करते हैं तो यह बहुत अच्छा है। वेडिंग प्लानर्स के पास धार्मिक समारोहों, पार्टियों और दिन-प्रतिदिन आयोजित होने वाले अन्य प्रकार के समारोहों में भी नौकरी के विकल्प होते हैं। उनके पास कैटरिंग, विज्ञापन और प्रमोशन में भी नौकरी की संभावनाएं हैं। वेडिंग प्लानर का वेतन वेडिंग प्लानर का वेतन शादी के पैमाने पर निर्भर करता है। आम तौर पर, इस क्षेत्र का एक पेशेवर औसतन शादी की लागत का 10% से 15% के बीच चार्ज कर सकता है। परामर्श शुल्क प्रतिभाओं और सेवाओं तथा वहां व्याप्त स्थानीय बाजार दोनों पर निर्भर करता है। वेडिंग प्लानर्स को शुरुआत में 15,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये प्रति माह तक का वेतन मिल सकता है। समय और अनुभव के साथ वे इससे कई गुना वार्षिक टर्नओवर वाला अपना उद्यम स्थापित कर सकते हैं।

सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शैक्षिक स्तंभकार मलोट

जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों की बढ़ेंगी मुश्किलें, RBI लाया 'मास्टर प्लान'

बैंक और एनबीएफसी समय-समय पर 25 लाख रुपये से अधिक बकाया रकम वाले सभी एनपीए खातों में विलफुल डिफॉल्ट के एंगल से जांच करेंगे। अगर उन्हें कोई गड़बड़ी नजर आती है तो वे खाते को एनपीए घोषित करने के 6 महीने के भीतर उधारकर्ता को विलफुल डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। फिर उनके खिलाफ आगे का एक्शन लिया जाएगा।

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने मंगलवार को विलफुल डिफॉल्टर्स और बड़े डिफॉल्टर्स की लगाम कसने के लिए मास्टर निर्देश जारी किया। इसके तहत बैंकों और एनबीएफसी को 25 लाख रुपये और उससे अधिक की बकाया राशि वाले सभी NPA (नॉन-परफॉर्मिंग असेट) खातों में 'विलफुल डिफॉल्ट' पहलू की जांच करनी होगी। इससे विलफुल डिफॉल्टर्स की पहचान करने और उनके खिलाफ एक्शन लेने में आसानी होगी।

क्या होता है विलफुल डिफॉल्टर का मतलब

विलफुल डिफॉल्टर का मतलब ऐसे कर्जदार या गारंटर से होता है, जो जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाता और डिफॉल्ट कर जाता है। हालांकि, इस स्थिति में विलफुल डिफॉल्टर उन्हीं को माना जाता है, जिनके ऊपर 25 लाख रुपये या इससे अधिक कर्ज होता है।

आरबीआई के मौजूदा निर्देश के अनुसार, बैंक और एनबीएफसी एक खास प्रक्रिया का पालन करके जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों की पहचान करेंगे और उन्हें 'विलफुल डिफॉल्टर' के रूप में वर्गीकृत करेगा। लेकिन, वह शख्स विलफुल डिफॉल्टर है या नहीं, इसकी जांच एक कमेटी करेगी।

कैसे होगी विलफुल डिफॉल्टर की पहचान

बैंक और एनबीएफसी समय-समय पर 25 लाख रुपये से अधिक बकाया रकम वाले सभी एनपीए खातों में विलफुल डिफॉल्ट के एंगल से जांच करेंगे। अगर उन्हें कोई गड़बड़ी नजर आती है, तो वे खाते को एनपीए घोषित करने के 6 महीने के भीतर उधारकर्ता को विलफुल डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।

लेनदेन में एनईएफटी से काफी अलग है यूपीआई, अंतर के साथ आसान भाषा में समझें

परिवहन विशेष न्यूज

UPI Vs NEFT अब हम बड़ी आसानी से चंद मिनटों में ऑनलाइन पैसे भेज सकते हैं। ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के लिए हम दो तरह के मोड का इस्तेमाल करते हैं। एक यूपीआई और दूसरा एनईएफटी है जिसके जरिये आसानी से ट्रांजैक्शन किया जाता है। यह दोनों मोड एक दूसरे से अलग होते हैं। आइए इस आर्टिकल में इन दोनों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

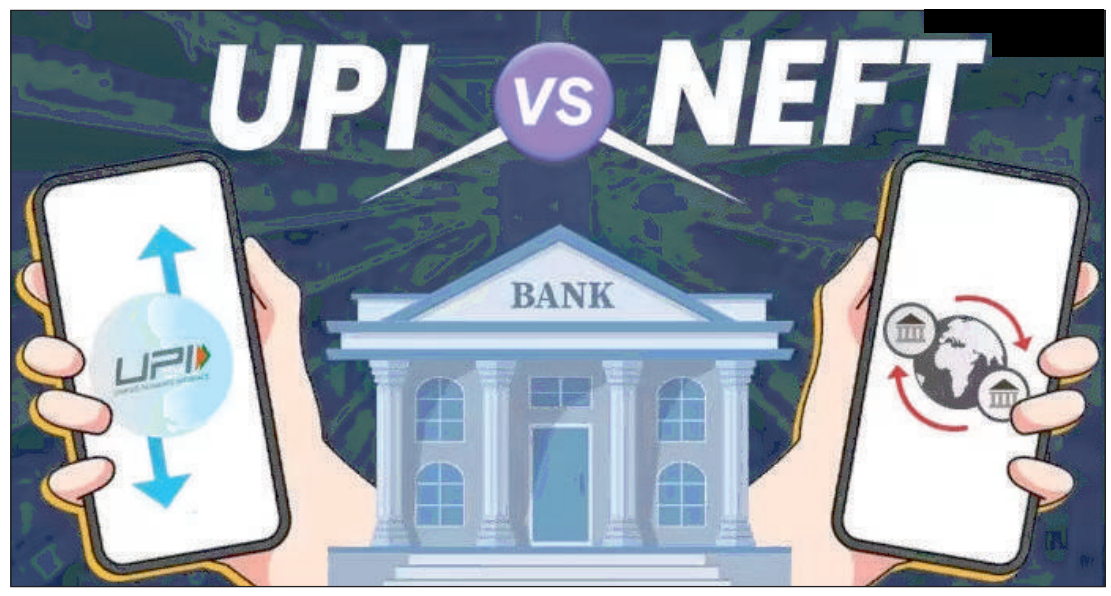

नई दिल्ली। टेक्नॉलजी ने एक हद तक हमारी लाइफ को आसान बना दिया है। अब हम टेक्नॉलजी की मदद से कई कामों को आसानी से कर सकते हैं। यहां तक कि जहां पहले हमें ट्रांजैक्शन करने के लिए बैंक जाते थे, अब हम आसानी से घर बैठे यह काम कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जब बात आती है तो सबसे पहला ध्यान यूपीआई (UPI) और एनईएफटी (NEFT) पर जाता है।

इन दोनों मोड से हम आसानी से फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। लेन-देन के लिए यह दोनों मोड एक दूसरे से काफी अलग है। आइए, इन दोनों मोड के अंतर के साथ इसके फायदे के बारे में विस्तार से समझते हैं।

UPI के बारे में

यूनिफाइट पेमेंट इंटरफेस (UPI) का इस्तेमाल आज हम किराने से लेकर बड़ी शॉपिंग के लिए भी करते हैं। मोबाइल रिचार्ज, बिजली बिल पेमेंट आदि काम हम बड़ी आसानी से यूपीआई के जरिये कर सकते हैं। अगस्त 2016 में नेशनल पेमेंट कॉर्प ऑफ इंडिया (NPCI) ने यूपीआई लॉन्च किया था। यूपीआई एक सिस्टम है जिसमें एक मोबाइल ऐप्स से कई बैंक अकाउंट लिंक किया जा सकता है।

आज डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में यूपीआई ने क्रांति ला दिया है। बैंकिंग फीचर्स के साथ फंड ट्रांसफर के लिए मिलने वाले फीचर की वजह से लोगों को यह पेमेंट ट्रांसफर सिस्टम काफी पसंद आ रहा है। यूपीआई इमिडिएट पेमेंट सर्विस (IMPS) प्लेटफॉर्म पर काम करता है। यह सर्विस 24X7 उपलब्ध होती है। इसका मतलब है कि यूजर्स कभी-भी, कहीं-भी बड़ी आसानी से यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं।

UPI के फायदे (Benefits of UPI app)

अब बात आती है कि यूपीआई ऐप के जरिये पेमेंट करने के क्या फायदे हैं। नीचे हमने यूपीआई के फायदे के बारे में बताया है:

- कहीं- भी, कभी-भी, कितनी बार भी आप बड़ी आसानी से चुटकी भर में यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं।
- यूपीआई ऐप्स में धोखाधड़ी को रोकने के लिए 2-factor authentication होता है।
- यूपीआई आईडी की मदद से आप आसानी से किसी भी बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर सकते हैं।
- यूपीआई से ट्रांजैक्शन के लिए आपको पर्सनल डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है।
- यूपीआई ऐप्स में आप एक के अलावा कई बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हर अकाउंट के लिए अलग ऐप्स की जरूरत नहीं है।
- ऑनलाइन और ऑफलाइन पेमेंट के लिए क्यू-आर कोड के जरिये आसानी से पेमेंट कर सकते हैं।
- यूपीआई में फंड सेटलमेंट तुरंत हो जाता है। फंड सेटलमेंट के लिए इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं होती है।
- अगर कोई शिकायत होती है तो उसके लिए भी कहीं जाना नहीं पड़ता है। आसानी से यूपीआई ऐप्स पर शिकायत किया जा सकता है।

NEFT के बारे में

नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) को नवंबर 2005 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुरू किया था। यह भी एक तरह का पेमेंट सिस्टम है जो पूरे राष्ट्र में लागू हुआ है। इसे भी जल्द से जल्द पेमेंट करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। एनईएफटी के जरिये आप आसानी से एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड ट्रांसफर कर सकते हैं।

एनईएफटी सर्विस का लाभ उठाने के लिए आपका बैंक अकाउंट भारत के किसी बैंक में होना चाहिए। यह सर्विस वर्किंग डे के दिन ही काम आती है। एनईएफटी सर्विस में मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट के लिए कोई लिमिट नहीं होता है। इसका मतलब है कि आप कितना भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं।

NEFT के फायदे (Benefits of NEFT)

- अब फंड ट्रांसफर करने के लिए फिजिकल चेक या डिमांड ड्राफ्ट की जरूरत नहीं है।
- NEFT में पैसे खो जाने या फिर फ्रॉड होने का खतरा नहीं होता है।
- यह पेपर वर्क को काफी कम कर देता है। दरअसल, बैंक जाकर फंड ट्रांसफर करने के लिए फॉर्म और कई पर्सनल डिटेल्स देने होते हैं। एनईएफटी में ऐसा नहीं होता है।
- अगर NEFT के जरिये फंड ट्रांसफर होता है तब मैसेज या मेल के जरिये कंफर्मेशन मिल जाता है।
- यह फाइनेंस पर कंट्रोल करने और जल्द से जल्द फंड ट्रांसफर करने का सही तरीका है।

यूपीआई और एनईएफटी दोनों अपने यूनीक फीचर और बेनिफिट की वजह से काफी पॉपुलर है। इन दोनों मोड के जरिये आज आप पूरे देश में कहीं भी बड़ी आसानी से चुटकी भर में पैसे भेज सकते हैं। यह कहना एकदम गलत नहीं होगा कि बैंकिंग सर्विस आपकी उंगलियों पर होगी।

एयर इंडिया के मर्जर से पहले विस्तारा ने शुरू की वीआरएस योजना, नॉन-फ्लाइंग स्टॉफ को मिलेगा लाभ

परिवहन विशेष न्यूज

सिंगापुर एयरलाइन की विस्तारा और टाटा ग्रुप की स्वामित्व वाली एयर इंडिया का मर्जर होने वाला है। मर्जर से पहले विस्तारा एयरलाइन ने नॉन-फ्लाइंग स्टाफ के लिए वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम (VRS) शुरू करने का एलान किया है। इस स्कीम का लाभ लाइसेंस धारक पायलट और केबिन क्रू को नहीं मिलेगा। एयर इंडिया ने भी इस महीने के शुरुआत में अपनी कर्मचारियों के लिए वीआरएस स्कीम शुरू किया था।

नई दिल्ली। विस्तारा (Vistara) और एयर इंडिया (Air India) का जल्द ही मर्जर होने वाला है। अभी तक दोनों एयरलाइन्स ने मर्जर के डेट की घोषणा नहीं की है, लेकिन मर्जर से पहले विस्तारा ने उड़ान सेवा के इतर अन्य कार्यों से जुड़े कर्मचारियों के लिए वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम (VRS) और वॉलेंट्री सेपरेशन स्कीम (VSS) की पेशकश की है। इसकी जानकारी एयरलाइन के अधिकारी ने दी है।

विस्तारा और एयर इंडिया के संयुक्त उद्यम होने वाले हैं। इस दोनों एयरलाइन्स में करीब 6,500 से अधिक कर्मचारी हैं।

नॉन-फ्लाइंग कर्मचारी को मिलेगा ऑप्शन

एयरलाइन अधिकारी ने बताया कि विस्तारा ने नॉन-फ्लाइंग स्थायी कर्मचारियों के लिए वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम (VRS) और वॉलेंट्री सेपरेशन स्कीम (VSS) की पेशकश की गई है। इस योजना का लाभ पाने के लिए कर्मचारी को 23 अगस्त तक आवेदन करना होगा।

वीआरएस योजना का लाभ उन लोगों के लिए है जिन्होंने एयरलाइन में पांच साल की सर्विस पूरी कर ली है, जबकि वीएसएस का लाभ उन कर्मचारियों के मिलेगा जिन्होंने एयरलाइन में अभी पांच साल की सेवा पूरी नहीं की है। ये योजना इस महीने की शुरुआत में टाटा समूह के स्वामित्व वाली एअर इंडिया के समान ही है।

इस योजना का लाभ पायलट, केबिन क्रू के मेंबर्स और लाइसेंस रखने वालों पर लागू नहीं होगी। अभी तक विस्तारा ने इसको लेकर कोई अधिकारिक टिप्पणी नहीं की है।

न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि इस महीने की शुरुआत में एअर इंडिया ने उड़ान सेवा के अलावा अन्य कार्यों से जुड़े कम से कम पांच साल तक की सेवा वाले स्थायी कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) पेश की है। वहीं, जो कर्मचारी पांच साल से कम समय से काम कर रहे उनके लिए स्वैच्छिक पृथक्करण योजना (वीएसएस) पेश किया गया।

क्या आठवें वेतन आयोग के गठन पर हो रहा विचार? सरकार ने संसद में दिया जवाब

केंद्र सरकार अमूमन हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करती है जिससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होता है। अभी 7वां वेतन आयोग लागू है जिसे साल 2016 में लागू किया गया था। सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी अब नए वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं और इससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है।

नई दिल्ली। सरकारी कर्मचारी लंबे समय से आठवें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं। उनका प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन भी लगातार इस मांग को उठा रहे हैं। अब सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन पर स्थिति साफ की है।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि आठवें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने कहा, 'आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए जून 2024 में दो अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इस समय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।'

आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन करती है। सातवें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था। इसकी सिफारिशें एक जनवरी 2016 से लागू की गईं। इस हिसाब से आठवें वेतन आयोग को एक जनवरी, 2026 को लागू किया जाना है।

8वें वेतन से 1 करोड़ कर्मचारियों को होगा लाभ

8वें वेतन आयोग के लागू होने से करीब 1 करोड़ कर्माचारियों को लाभ मिलेगा। इसमें लगभग 49 लाख कर्मचारी और 68 लाख पेंशनभोगी हैं। अगले वेतन आयोग से कर्मचारियों को मिलने वाले फिटमेंट फैक्टर में इजाफा होगा। इससे उनकी सैलरी बढ़ जाएगी। फिटमेंट फैक्टर से कर्मचारियों की सैलरी और पे मैट्रिक्स निकालने में मदद मिलती है।

7वें वेतन आयोग में 2.57 गुना फिटमेंट फैक्टर पेश गया था। इससे सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में करीब 14.29 फीसदी की वृद्धि हुई थी और उनकी बेसिक सैलरी करीब 18,000 रुपये हो गई थी। जानकारों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर लगभग 3.68 गुना हो सकता है। अगर इतना फिटमेंट फैक्टर होता है, तो कर्मचारियों की सैलरी में करीब 8,000 रुपये की वृद्धि होगी।

चीन से FDI को बढ़ावा देने पर पुनर्विचार नहीं, तनाव के बीच तेजी से बढ़ रहा द्विपक्षीय व्यापार

भारत सरकार चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को बढ़ावा देने पर किसी तरह का पुनर्विचार नहीं कर रही है। दोनों देशों के बीच तनाव के बावजूद भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार तेजी से बढ़ा है। विवादों के बीच 2023-24 में 118.4 अरब डालर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनकर उभरा है।

नई दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि सरकार चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को बढ़ावा देने पर किसी तरह का पुनर्विचार नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में इस संबंध में आर्थिक सर्वेक्षण में जो कुछ भी कहा गया है, वह सिर्फ नए विचारों का प्रतिनिधित्व करती है।

इन देशों के लिए एफडीआई अनिवार्य

गोयल ने कहा कि सर्वेक्षण में कही गईं बातें सरकार के लिए बिल्कुल भी बाध्यकारी नहीं हैं। सरकार ने 2020 में भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों से एफडीआई के लिए उसकी मंजूरी अनिवार्य कर दी थी। भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देश चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमा और अफगानिस्तान हैं।

चीन के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बीच संसद में 22 जुलाई को पेश बजट-पूर्व आर्थिक समीक्षा 2023-24 में स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और निर्यात बाजार का दोहन करने के लिए पड़ोसी देश चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) बढ़ाने की वकालत की गई थी।

गोयल ने इसी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यह बयान दिया है। सर्वेक्षण में कहा गया था कि अमेरिका और यूरोप अपनी तात्कालिक आपूर्ति चीन से हटा रहे हैं, इसलिए पड़ोसी देश से आयात करने के बजाय चीनी कंपनियों द्वारा भारत में निवेश करना और फिर इन बाजारों में उत्पादों का निर्यात करना अधिक प्रभावी है।

अब म्यूचुअल फंड में नहीं होगी गड़बड़ी! इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए 1 नवंबर से लागू होंगे सख्त नियम

मार्केट रेगुलेटर इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए नए नियम ला रहा है जो 1 नवंबर से प्रभावी होंगे। ये नियम उन कर्मचारियों के लिए होंगे जिनके पास संवेदनशील जानकारियां होंगी। ऐसे शख्स को नामित व्यक्ति (देसिग्नेटेड पर्सन) कहा जाएगा। इन सभी को गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे कि ये किसी भी संवेदनशील जानकारी को दूसरों के साथ साझा नहीं करेंगे।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। शेयर मार्केट में इनसाइडर ट्रेडिंग या फिर फ्रंट रनिंग जैसे शब्द अक्सर सुनाई देते हैं। खासकर, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। कई बार फंड हाउस से जुड़े लोगों पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने गोपनीय जानकारियों का इस्तेमाल करके पैसे कमाए हैं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर पारदर्शिता न बरतने के आरोप भी लगते हैं। लेकिन, अब ऐसा नहीं होगा।

दरअसल, मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सख्त नियम ला रहा है। इसमें खासकर इनसाइडर ट्रेडिंग पर लगाम लगाने का प्रावधान है। आइए जानते हैं कि नए नियमों का क्या असर होगा।

गोपनीयता समझौते पर करना होगा साइन

शेयर मार्केट एक्सपर्ट के मुताबिक, सेबी का नया नियम उन कर्मचारियों के लिए होगा, जिनके पास प्राइस सेंसिटिव यानी किसी कंपनी के शेयर के दाम घटने या बढ़ने जैसी जानकारी होगी। ऐसे शख्स को नामित व्यक्ति (Designated Person) कहा जाएगा। इन सभी को गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे कि ये किसी भी संवेदनशील जानकारी को साझा नहीं करेंगे।

रिश्तेदारों की होल्डिंग भी बतानी होगी

सेबी ने 26 जुलाई को नए नियमों को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया। इसके मुताबिक, प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रखने वाले अब म्यूचुअल फंड यूनिट की ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। साथ ही, असेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी) को बताना होगा कि म्यूचुअल फंड स्कीम में ट्रस्टी और उनके रिश्तेदारों की होल्डिंग कितनी है। नामित व्यक्ति के ट्रांजेक्शन की जानकारी भी दो दिन के भीतर देनी होगी।

अंदरूनी कंट्रोल की होगी समीक्षा

नए इनसाइडर ट्रेडिंग नियम 1 नवंबर, 2024 से प्रभावी होंगे। इसके तहत एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को अपने अंदरूनी कंट्रोल की समय-समय पर समीक्षा भी करनी होगी। सेबी इन नियमों को लंबे समय से लागू करना चाहता था। उसने जुलाई, 2022 में इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर कंसल्टेशन पेपर भी जारी किया। लेकिन, इंडस्ट्री के विरोध के चलते नए नियमों को लागू करने में देरी हुई।

एक महान योद्धा भगवान्ना पहलवान

परिवहन विशेष न्यूज

भगवानना की 7 फिट की उचाई उस समय भी लोगो के आकर्षण का केन्द्र हुआ करती थी । धोबी पाट और घिस्सा दॉव भगवान्ना के मुख्य दॉव थे ।

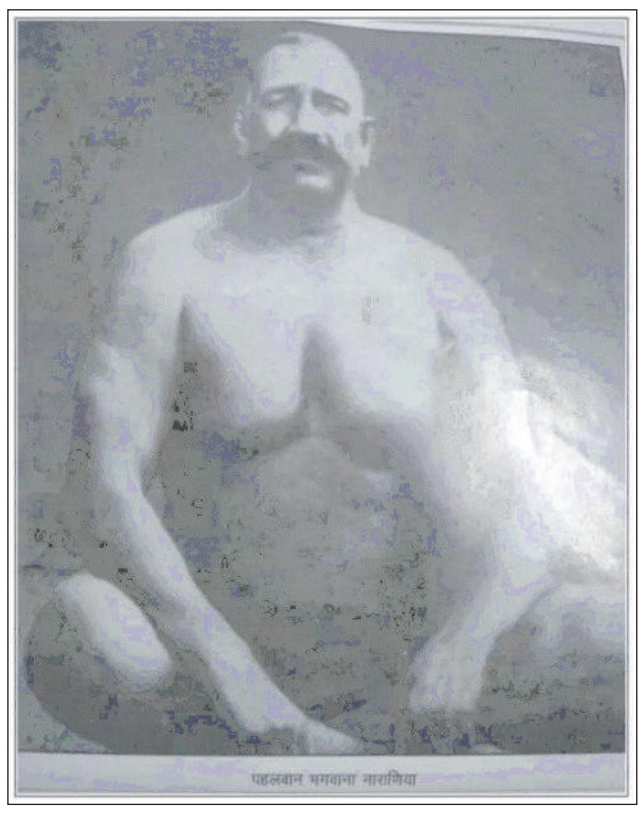
पहलवान भगवाना नारायिया

भगवान्ना पहलवान का जन्म 1885 मे नारायणा गॉव मे हुआ था । यह गॉव कभी दिल्ली के पास हुआ करता था । अग्रेजी राज हुआ करता था 18 साल की उम्र मे भगवान्ना पहलवान पुलिस मे भर्ती हो गये । भगवानना की 7 फिट की उचाई उस समय भी लोगो के आकर्षण का केन्द्र हुआ करती थी । धोबी पाट और घिस्सा दॉव भगवान्ना के मुख्य दॉव थे । एक समय का जिकर है । भगवाना पहलवान की युनिट कोलम्बो श्रीलंका चली गई जहा पर लोगो ने भगवान्ना को पहचान लिया क्यो कि वहॉ के लोगो ने इससे पहलें भगवान्ना का केवल नाम सुन रखा था आज साक्षात देख लिया । उनही दिनो महान पहलवान राममूर्ती भी श्री लंका आया हुआ था । राममूर्ती ने भगवान्ना को कुस्ती के लिये ललकार दिया । भगवान्ना ने राममुर्ती की चुनौती स्वीकार करली राममूर्ती भी राजा का माल था । जब यह बात अंग्रेजो को पता चली तो अंग्रेजो ने भगवान्ना को कुस्ती ना लडने का फरमान सुना दिया तथा एक कमरे मे बन्द करदिया । अब भगवाना के मन मे एक विचार आया की यदि मै रामूर्ती से कुस्ती लडने ना गया तो लोग सोचेगे की भगवान्ना पहलवान डर गया है। जिस कमरे मे भगवान्ना पहलवान बन्द था भगवान्ना ने उस कमरे की एक खिडकी को उखाड लिया और चुप चाप कुस्ती लडने के लिये चला गया 40 वे मिन्ट मे भगवान्ना ने राममूर्ती को चित कर दिया । उस समय राममूर्ती और भगवान्ना की कुस्ती पर 5000(पॉच हजार) रूपये का इनाम रखा गया था जो भगवान्ना को दिये गये साथ साथ कुस्ती प्रेमियों ने मिलकर 1700 रू इक्टठा कर भगवान्ना को दिये । अग्रेजो की बात ना मानने का परिणाम यह हुआ आज भगवान्ना को सस्पेन्ड कर दिया गया । नौकरी छूटने के बाद भगवान्ना अपने गॉव आ गया और शिव मन्दिर मे जोर आजमाईश किया करता एक दिन भगवाना अपनी किसी रिस्तेदारी मे जा रहा था 1 .....पैदल के रास्ते हुआ करते भगवान्ना को रास्ते मे प्यास लग गई रास्ते मे कुवे पर चडस रखा हुआ था जिसे दो बैल खीचा करते लेकिन वहॉ बैल नही थे तो भगवान्ना ने चडस को कुवे मे छोड पानी से भर जाने के बाद दोनो हाथो से खीचना आरम्भ कर दिया उसी समय एक राजा का एक वजीर वहा से गुजर रहा था उसने जब सात फिट उचे भीमकाय भगवान्ना को चडस खीचते हुये देखा तो वो वजीर भगवान्ना के पास आया । भगवान्ना ने चडस खीचकर पानी पिया व स्नान किया । बाद मे वह वजीर भगवान्ना को अपनी जान पहचान के एक मुसलमान रियासतदार जो कुस्ती प्रेमी था के पास लाहोर मे छोड आया । भगवान्ना का ज्यादा दिन लाहोर मे मन नही लगा और एक साल बाद महाराष्ट्र मे कोल्हापुर आ गया । क्योकि कोल्हा पुर का1 महाराज भी कुस्ती प्रेमी था और नौकरी करने के दौरान ससपेन्ड होने से पहले कोलहापुर के महाराज से भगवान्ना की जान पहचान हो गई थी । कोल्हापुर के महाराज ने भगवान्ना को बहुत इज्जत दी और अपना दरवारी पहलवान घोषित कर दिया । भगवान्ना उम्र मे गामा पहलवान से 15 - 16 साल बडे थे । कहा जाता है। की एक बार गामा और भगवान्ना की कुस्ती हुई जिसमे भगवान्ना की ऑख के उपर चोट लग गई तथा लहू की धारा बह निकली जिसके बाद भगवान्ना ने गामा को उठाकर अखाडे के बहार पटक दिया यही पर इस कुस्ती मे विवाद हो गया और गामा के भाई ने गामा को लडने से मना कर दिया गामा ने यह कुस्ती बीच मे छोडदी जिसके बाद भगवान्ना को विजयी घोषित किया गया । महाराज ने खुश होकर भगवान्ना को सरकारी सम्मान के साथ साथ सोने के दो कडे और सोने के सिक्को से भरा एक थेला भेट किया यह घटना राम सिंह रावत की किताब (रवा राजपूतो का इतिहास के प्रथम खण्ड मे भी दर्ज है।)कुछ दिन बीते थे की राजा के राज मे एक शेर आ गया महाराज ने अपने पहलवानो और कुछ सैनिको की सहायता से जिस खेत मे शेर छिपा था वो खेत घेर लिया अपने आप को घिरता देख शेर जैसे ही राजा की और लपका तो भगवानना ने शेर की कमर मे लाठी मार दी भगवान्ना की लाठी का वार इतना जोर दार था कि शेर का हाड बीच मे से टूट गया कुछ देर बाद शेर ने तडफकर दम तोडदिया । महाराज ने भगवान्ना को गले से लगा लिया जब यह बात महारानी को पता चली तो महारानी ने भगवान्ना के पैर छूने की इच्चछा जाहिर की थी हालाकि भगवान्ना ने एसा ना करने के लिये रानी से विनती की एक बार भगवान्ना अपने गॉव मे आये हुये थे भगवान्ना के खेत मे एक खेत एसा था जहा पर चारो और हरी फसल लहला रही थी पत्थर की कोहलडी को ले जाने मे बहुत सारी फसल नष्ट हो जाती तो मौके की नजाकत को देख भगवान्ना ने पत्थर की कोहलडी को जिसे खीचकर दो बैल चलते थे उसे कन्धे पर रख कर खेत मे पटक दिया था आज बेसक भगवान्ना पहलवान के स्वर्णिम नाम को समय की गरद ने दवा दिया हो हममे से कई लोग आज भगवान्ना पहलवान के बारे मे ना जानते हो लेकिन एक दौर एसा था कि जिसमे माये रात को अपने बच्चो को भगवान्ना पहलवान की बहादुरी के किस्से सुनाती थी । आओ मिलकर इस महान योद्धा को नमन करे ।

कोलोस्ट्राल का आयुर्वेदिक इलाज

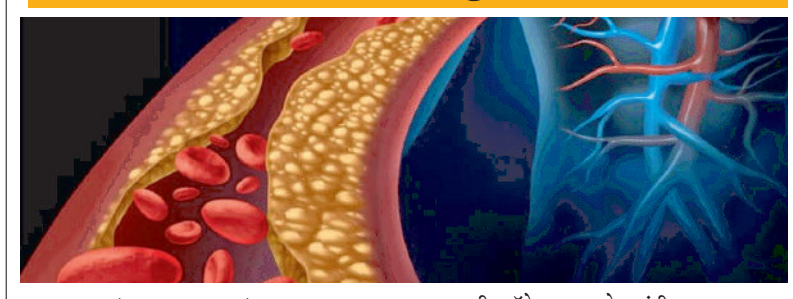

अदरक (ginger juice) -
यह खून को पतला करता है।
यह दर्द को प्राकृतिक तरीके से 90% तक कम करता हें।
लहसुन (garlic juice)
इसमें मौजूद allicin तत्व cholesterol व BP को कम करता है।
वह हार्ट ब्लॉकेज को खोलता है
नींबू (lemon juice)
इसमें मौजूद antioxidants, vitamin C व potassium खून को साफ़ करते हैं।
ये रोग प्रतिरोधक क्षमता (immunity) बढ़ाते हैं।
एप्पल साइडर सिरका (apple cider vinegar)
इसमें 90 प्रकार के तत्व हैं जो शरीर की सारी नसों को खोलते है, पेट साफ़ करते हैं व थकान को मिटाते हैं।

इन देशी दवाओं को इस तरह उपयोग में लेवें

1-एक कप नींबू का रस लें;
2-एक कप अदरक का रस लें;
3-एक कप लहसुन का रस लें;
4-एक कप एप्पल का सिरका लें;
चारों को मिला कर धीमीं आंच पर गरम करें जब 3 कप रह जाए तो उसे ठण्डा कर लें;
अब आप
उसमें 3 कप शहद मिला लें
रोज इस दवा के 3 चम्मच सुबह खाली पेट लें जिससे
सारी ब्लॉकेज खत्म हो जाएंगी।
जरा सोचिये की शाम के
7:25 बजे है और आप घर जा रहे है वो भी एकदम अकेले।
ऐसे में अचानक से आपके सीने में तेज दर्द होता है जो आपके हाथों से होता हुआ आपके जबड़ो तक पहुँच जाता है। आप अपने घर से सबसे नजदीक अस्पताल से 5 मील दूर है और दुर्भाग्यवश आपको ये नहीं समझ आ रहा की आप वहां तक पहुँच पाएंगे की नहीं। आप सीपीआर में प्रशिक्षित है मगर वहां भी आपको ये नहीं सिखाया गया की इसको खुद पर प्रयोग कैसे करे।

ऐसे में दिल के दौरे से बचने के लिए करे यह उपाय

चूँकि ज्यादातर लोग दिल के दौरे के वक्त अकेले होते है बिना किसी की मदद के उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है । वे बेहोश होने लगते है और उनके पास सिर्फ 10 सेकण्ड्स होते है। ऐसे हालत में पीड़ित जोर जोर से खांस कर खुद को सामान्य रख सकता है। एक जोर की सांस लेनी चाहिए हर खांसी से पहले और खांसी इतनी तेज हो की छाती से थूक निकले। जब तक मदद न आये ये
प्रक्रिया दो सेकंड से दोहराई
जाए ताकि धड़कण सामान्य
हो जाए । जोर की साँसे फेफड़ो में ऑक्सीजन पैदा करती है
और जोर की खांसी की वजह
से दिल सिकुड़ता है जिस से
रक्त सञ्चालन नियमित रूप से
चलता है ।

कोरोना पीड़ितों के हो सकते हैं कई अंग प्रभावित, मानसिक स्वास्थ्य पर भी भयंकर असर; स्वास्थ्य राज्यमंत्री दी जानकारी

वैश्विक महामारी कोविड-19 के बाद की जटिलताओं से पीड़ितों के कई अंग प्रभावित हो सकते हैं ।केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव ने राज्यसभा में यह बात कही। उन्होंने कहा कि कोविड से पीड़ित रह चुके लोगों को थकान और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें हो सकती हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि एक्यूपंक्चर के लिए एक नियामक प्रणाली बनाने की सिफारिश पर सरकार विचार कर रही है।

नईदिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव ने राज्यसभा को बताया कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के बाद की जटिलताओं से पीड़ितों के कई अंग प्रभावित हो सकते हैं। कोविड से पीड़ित रह चुके लोगों को थकान और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें हो सकती हैं। इसके साथ ही फेफड़े, हृदय, रक्त संबंधी, तंत्रिका-मनोविकार, त्वचा संबंधी, किडनी संबंधी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या इंडोक्रिनिल संबंधी रोग हो सकते हैं।

पीड़ितों को हो सकती हैं कई परेशानियां

स्वास्थ्य राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव ने मंगलवार को बताया कि आईसीएमआर के अनुसार, कोविड-19 के नेशनल क्लीनिकल रजिस्ट्री के अनुसार देश भर के 31 अस्पतालों से मिले आंकड़ों के मुताबिक वैश्विक महामारी से पीड़ित रहे लोगों को श्वसन संबंधी बीमारी, थकान और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए अस्पताल से डिस्चार्ज होने के 30-60 दिनों के बाद ऐसे लक्षण दिखने पर फॉलोअप कराना चाहिए।

आयुष को मुख्यधारा में लाने की तैयारी

इसी तरह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि एक्यूपंक्चर के लिए एक नियामक प्रणाली बनाने की सिफारिश पर सरकार विचार कर रही है। आयुष मंत्रालय ने इस संबंध में कई विभागों से संपर्क किया है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आयुष को सरकार मुख्यधारा में लाने की रणनीति बना रही है। इसके तहत आयुर्वेद, योग, नैचुरोपैथी, होम्योपैथी आदि आते हैं।

इन राज्यों में दर्ज हुए जीका वायरस के मामले

स्वास्थ्य राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि इस साल 22 जुलाई तक जीका वायरस के महाराष्ट्र में दस व कर्नाटक में तीन मामले दर्ज हुए हैं। वायु प्रदूषण से बीमारी या मौत होने का कोई सीधा संबंध होने के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

पंजाब सरकार को जारी किए गए हैं 1.49 करोड़ रुपये

अनुप्रिया पटेल ने बताया कि पंजाब सरकार आयुष्मान भारत-हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं कर रही है। इस संबंध में पंजाब सरकार को 91.49 करोड़ रुपये जारी भी किए जा चुके हैं।

एम्स के मरीजों के लिए अच्छी खबर, चलेंगी AC लो फ्लोर ई-बसें; 40 हजार लोगों को मिलेगा फायदा

दिल्ली एम्स में इलाज कराने आने वाले मरीजों के लिए खुशखबरी है। एम्स के निदेशक ने अस्पताल प्रशासन को आउटसोर्स के माध्यम से ठेके पर एसी लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसें लेने का आदेश दिया है। अगर यह योजना सफल होती है तो एम्स मेट्रो स्टेशन से मरीजों को अस्पताल के ओपीडी ब्लॉक सहित कई सेंटर तक पहुंचने में आसानी होगी। इससे कई हजार लोगों को फायदा होगा।

नई दिल्ली। एम्स के निदेशक डा. एम श्रीनिवास ने अस्पताल प्रशासन को आउटसोर्स के माध्यम से ठेके पर एसी लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसें लेने का निर्देश दिया है। मंगलवार को ही इसके लिए आदेश जारी किया है। यदि इस योजना पर अमल हुआ तो एम्स में वातानुकूलित लो-फ्लोर ई-बसें चलेंगी।

इन बसों में सीट से अधिक नहीं चढ़ पाएंगे लोग

जिसमें 20 मरीजों और उनके तीमारदारों के बैठने की सुविधा होगी। इससे एम्स मेट्रो स्टेशन पर उतरने के बाद मरीजों को अस्पताल के ओपीडी ब्लॉक सहित विभिन्न सेंटर तक पहुंचने में आसानी होगी। इन बसों में सीट से अधिक लोग नहीं चढ़ पाएंगे।

मौजूदा समय में एम्स में निशुल्क ई-शटल सेवा का परिचालन होता है। एम्स के गेट नंबर एक से मस्जिद मोठ तक इन शटल बसों का परिचालन होता है। मस्जिद मोठ के पास नए ओपीडी ब्लाक, सर्जरी ब्लाक, मातृ एवं शिशु ब्लाक व राष्ट्रीय वृद्धजन केंद्र स्थित है।

एम्स करीब 30 छोटे शटल बसों का करता है परिचालन

शटल सेवा के रूप में एम्स करीब 30 छोटे शटल बसों का परिचालन करता है। एम्स की ओपीडी में प्रतिदिन करीब 13,500 मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। इसके अलावा जांच के लिए भी काफी संख्या में मरीज पहुंचते हैं। हर मरीज के साथ एक से दो स्वजन होते हैं। ऐसे में एम्स में प्रतिदिन करीब 40 हजार लोगों पहुंचते हैं।

इस वजह से शटल सेवा की सुविधा कम पड़ रही है। आदेश में कहा गया है कि एम्स करीब 200 एकड़ में फैला हुआ है। मेट्रो स्टेशन और बस स्टैंड के पास उतरने के बाद मरीजों और उनके स्वजनों को ट्रामा सेंटर व मस्जिद मोठ के पास स्थित कैंपस में जाने के लिए काफी चलना पड़ता है।

इन बसों में होगी जीपीएस की व्यवस्था

इसके अलावा बहुत मरीज और उनके स्वजन आटो से ट्रामा सेंटर, ओपीडी ब्लॉक, मातृ एवं शिशु ब्लॉक, सर्जरी ब्लॉक व राष्ट्रीय वृद्धजन केंद्र जाने को मजबूर होते हैं। इससे एम्स में ट्रैफिक की समस्या होती है। इसके मद्देनजर आउटसोर्स के जरिये ई-बसें लेने का आदेश दिया है। आदेश में एम्स के परिसर में जगह-जगह शेड वाले बस स्टैंड बनाने बनाने व एक मोबाइल ऐप भी जारी करने का निर्देश दिया गया। ये ई-बसें जीपीएस से लैस होंगी।

आदेश में कहा गया है कि बस स्टैंड पर एक बटन होगा, जिसे दबाने पर ई-बस चालक को पता चल सकेंगे कि स्टैंड पर मरीज इंतजार कर रहे हैं। प्रत्येक कार्य दिवस के दिन सुबह सात से रात दस बजे तक हर दस मिनट के अंतराल पर ई-बसें उपलब्ध होंगी।

शाम सात से सुबह सात बजे के बीच 15 मिनट के अंतराल पर यह बसें चलेंगी। इन बसों में सफर का किराया तय होगा। यूपीआइ या एम्स स्मार्ट कार्ड से किराया भुगतान किया जा सकेगा।

आईओसीएल टर्मिनल में आग पर हुई मेगा मॉक ड्रिल

फायर ब्रिगेड , सिविल डिफेंस मथुरा एवं एनडीआरएफ की टीमों ने संभाला मोर्चा*
आपदा प्रबंधन को लेकर राहत व बचाव कार्यों का हुआ अभ्यास

मथुरा : इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मथुरा में मंगलबार सुबह उस वक्त गहमागहमी हो गई, जब एकाएक सायरन बजाते हुए फायर ब्रिगेड की गाड़ी परिसर में दाखिल हुई और उसके पीछे सिविल डिफेंस मथुरा एवं एनडीआरएफ और स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी-कर्मचारी भी राहत और बचाव कार्य के लिए अंदर आ गए। मौका था इंडियन ऑयल में मेगा मॉक ड्रिल का। जिला प्रशासन द्वारा आग पर काबू पाने और राहत एवं बचाव कार्य को सिरे चढ़ाने के विषय पर इस मेगा मॉक ड्रिल को संचालित किया गया। सिविल डिफेंस और दमकल विभाग के साथ-साथ आईओसीएल प्रबंधन द्वारा स्थापित किए गए सुरक्षा उपकरणों से भी आग पर काबू पाने के लिए डीजल टैंक पर जोरदार बौछार की गई। इसके साथ ही सिविल डिफेंस मथुरा और एनडीआरएफ की टीमों द्वारा मॉक ड्रिल के दौरान प्रभावितों के लिए राहत और बचाव कार्य को भी सिरे चढ़ाया गया। सभी घायलों को आईओसीएल प्लांट में ही स्थापित किए गए फस्ट एड कैंप तक ले जाया गया। जो ज्यादा घायल थे उनको एम्बुलेंस के माध्यम से नजदीकी हॉस्पिटल में स्टेचर के माध्यम से एंबुलेंस में भेजा गया ।

नागरिक सुरक्षा विभाग मथुरा के उप नियंत्रक जसवंत सिंह ने बताया कि सरकार के निर्देश पर आपदा प्रबंधन की दृष्टि से इस मेगा मॉक ड्रिल के संचालन का आयोजन किया गया है, जिसमें आग पर काबू पाने के साथ प्रभावित लोगों के राहत और बचाव कार्य का अभ्यास भी करवाया गया। सिविल डिफेंस मथुरा के सहायक उप नियंत्रक जितेन्द्र देव सिंह ने कहा कि इस तरह के इवेंट्स का आयोजन अधिकारियों-कर्मचारियों को आपदा प्रबंधन के गुर सिखाने के साथ-साथ आम जनमानस को भी आपदा की स्थिति से निपटने के लिए तैयार करने हेतु किया जाता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जनरल मैनेजर के. गोपीनाथ ने कहा कि मेगा मॉक ड्रिल का संचालन सफलतापूर्वक किया गया है, जिसमें जिला प्रशासन के नेतृत्व में सिविल डिफेंस मथुरा और एनडीआरएफ एवं विभिन्न विभागों और आईओसीएल प्लांट प्रबंधन द्वारा भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई। उसी दौरान सिविल डिफेंस मथुरा के पोस्ट वार्डन अशोक यादव के द्वारा सेल्फ कंटेंड ब्रीदिंग आपरेटस सेट के साथ घायलों को फायर मेन लिफ्ट के माध्यम से निकला और साथ में दमकल विभाग के जवानों ने भी घायलों को निकाल कर उपचार हेतु नजदीकी हॉस्पिटल में भेजा गया। मॉक ड्रिल में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के कर्मचारीयों के साथ एनडीआरएफ अकैडमी और सिविल डिफेंस मथुरा के डिविजनल वार्डन भारत भूषण तिवारी, डिप्टी डिविजनल वार्डन राजेश कुमार मित्तल, सीनियर स्टाफ ऑफीसर टू चीफ वार्डन दीपक चतुर्वेदी बैंकर, पोस्ट वार्डन अशोक यादव, अरविंद कुमार, वर्षा, हेमंत, राम सैनी, नरेश अग्रवाल, ऋषभ प्रताप सिंह, गुलशेर, अरुण, विक्रम, गिरीश कुमार, राकेश, नरेन्द्र मोहन मेहता, मुशीर अहमद, राजेंद्र सैनी, शाहिद बाबू, अंबुज, शैलेश, जवर सिंह, आदि वार्डन और फायर फाइटर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मथुरा रिफायनरी में मॉक ड्रिल में अपना सहयोग प्रदान किया गया।

ओड़िशा हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि जहाज को तुरंत गिरफ्तार किया जाए

मनोरंजन सासमल , स्टेटे हेड उडीशा

भुबनेस्वर : ओडिशा उच्च न्यायालय ने जहाज (MV ZHE HI 505 (IMO No.-9567477)) को पारादीप बंदरगाह में गिरफ्तार करने का आदेश दिया है, यदि गिरफ्तारी आदेश जारी नहीं किया जाता है, तो जोखिम है कि जहाज पारादीप बंदरगाह छोड़ देगा। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि जहाज को तुरंत गिरफ्तार किया जाए ।आवेदक को उच्च न्यायालय के इस आदेश की एक प्रति पत्र, मेल, फैक्स या व्यक्तिगत रूप से उच्च न्यायालय मार्शल के साथ भेजनी होगी। आगे यह निर्देशित किया जाता है कि आवेदक अगले 24 घंटों के भीतर गिरफ्तारी के इस वारंट की तामील करेगा। जब जहाज मालिक ने आवेदक फर्म स्कांडी ट्रेडिंग लिमिटेड को 99 लाख 81 हजार 553 रुपये का भुगतान नहीं किया, तो उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी । सोमवार को सुनवाई के बाद नरसिंह ने उक्त आदेश दिया । अगली सुनवाई अगस्त में होनी है । नौवाहनविभाग कानून के आधार पर जहाज को गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जाएगी।

मामले के मुताबिक याचिकाकर्ता ट्रेडिंग कंपनी और शिपिंग अथॉरिटी दोनों के बीच 'लो सल्फर मरीन गैस ऑयल' के लेनदेन को लेकर विवाद था ।जहाज के मालिक को ट्रेडिंग कंपनी को 99 लाख 81 हजार 553 रुपये का भुगतान करना होगा । लेकिन जब जहाज मालिक ने राशि का भुगतान नहीं किया तो याचिकाकर्ता ट्रेडिंग कंपनी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। यह मामला नौवाहनविभाग अधिनियम (समुद्री दावों का क्षेत्राधिकार और निपटान)-2017 की धारा (4)(1)(i) के तहत लाया गया था।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023